



R-2018

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35]
No. 35]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 1989/फाल्गुन 9, 1910
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 1989/PHALGUN 9, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

बजट प्रभाग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी 1989

वित्त (आ का वि.) यू.ओ.नं. 15 (95) व. (प्र.)/
88—निम्न लिखित को सर्व साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित
किया गया :—

बजट 1989-90

वित्त मंत्री

श्री एस. बी. चट्टोपाध्याय

का

भाषण

28 फरवरी, 1989

भाग 'क'

महोदय,

मे वर्ष 1989-90 के लिए बजट प्रस्तुत करने के वास्ते
उपस्थित हुआ हूँ। एक सुनियोजित विकास के बुनियादी

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जिनमें मुख्यतः विकास, आधुनिकी-
करण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय शामिल है, बजट
एक साधन का काम करता है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में
हमने बहुत प्रगति की है। नवें दशक के दौरान हमारी
अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि की दर में तेजी आने के स्पष्ट संकेत
विद्यमान हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने जिन नीतियों का
अनुसरण किया है उनके फलस्वरूप आधुनिकीकरण की गति
में, विशेष रूप से उद्योग और आधारभूत ढांचे की गति में
अत्यन्त वृद्धि हुई है। निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि से
आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयास बराबर कायम रहे
हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबी-
विरोधी तथा रोजगार-कार्यक्रमों और अनिवार्य आवश्यकताओं
की पूर्ति के लिए हमने जो प्रमुख उपाय किए हैं उनमें
सामाजिक न्याय के लक्ष्यों के प्रति हमारी वचनबद्धता स्पष्ट
झलकती है। वर्ष 1989-90 का बजट तैयार करने में ये
दीर्घावधिक उद्देश्य आधार हैं।

2. असाधारण आर्थिक स्थिति के संदर्भ में ही इन
दोषवर्षिक उद्देश्यों का वार्षिक बजट में अनुसरण किया
जाता है। अभी कुछ दिन पहले सदन के पटल पर रखी

गई वर्ष 1988-89 का आर्थिक समीक्षा में, आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ विस्तार से वर्षों की गई है। मैं उनमें से केवल कुछों का ही जिक्र करूंगा।

3. पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था के कार्य-निष्पादन में निःसंदेह मजबूती के लक्षण दिखाई दिए हैं। पहला यह है कि गम्भीर सूखे और बाढ़ की स्थिति में उत्पन्न अव्यवस्था के बावजूद अर्थ-व्यवस्था में लचीलापन होना बना रहा है। पिछले वर्ष, मेरे पूर्ववर्ती ने, बजट प्रस्तुत करते समय इसका उल्लेख किया था और यह संकेत दिया था कि सकल घरेलू उत्पाद में सम्भवतः 1 से 2 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी है कि सूखे के वर्ष 1987-88 में अधिक कार्य निष्पादन के नवीनतम अनुमानों से यह पता चलता है कि सूखे के बावजूद, सकल घरेलू उत्पाद में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सूखे के वर्ष में इस सराहनीय कार्य निष्पादन के बाद चालू वर्ष में हुई तेज प्रगति से उम्मीद है कि सकल घरेलू उत्पाद में वस्तुतः 9 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की वृद्धि होगी। सूखे के वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर तथा सूखे के बाद के वर्ष में प्राप्त हुई प्रगति की दर, दोनों ही सूखे की पिछली अवधियों की दरों के मुकाबले काफी अधिक है। मैं यह बता दूँ कि योजना के पहले चार वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 5 प्रतिशत के योजना लक्ष्य से अधिक होगी।

4. इन विगत दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में हुए कार्य निष्पादन से आशाएँ बंधने लगी हैं। पिछले वर्ष, गम्भीर सूखे और बाढ़ के बावजूद, खाद्यान्न का उत्पादन 1380 लाख मी. टन हुआ, जो उससे पिछले वर्ष के उत्पादन से मामूली सा कम है, जिसमें वह पता चलता है कि सूखे को नियंत्रण में रखने के लिए हमारे द्वारा अपनाई गई नीतियाँ सफल रही। इस वर्ष, उम्मीद है कि खाद्यान्न 1660 उत्पादन लाख मी. टन के लक्ष्य को पार कर जाएगा। आशा है कि तेलहन, कपास और चीनी का उत्पादन रिकार्ड स्तर पर पहुँच जाएगा। इस क्षेत्र में विकास की उंची क्षमता के लक्षण बने हुए हैं।

5. दबावपूर्ण कठिन समय में उत्पादन में वृद्धि, सरकार द्वारा खाद्य अर्थ-व्यवस्था का सावधानीपूर्वक प्रबंध और कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए किए गए विशेष उपायों के परिणाम-स्वरूप थोक कीमत सूचकांक द्वारा यथामापित मुद्रास्फीति की दर, 1987-88 में 10.6 प्रतिशत तक ही सीमित रही। चालू वर्ष में मुद्रास्फीति की दर, जनवरी 1989 के अंत तक घटकर 5 प्रतिशत से कम रह गई है। कीमतों पर जो दबाव बना हुआ है उसके प्रति सरकार चिन्तित है। परन्तु यह कुछ संतोष की बात है कि यह दबाव पूर्ववर्ती सूखों की अपेक्षा सामान्य रूप से कम है। सरकार इस महत्वपूर्ण विषय के प्रति दबाव पूर्णतः जागरूक है और और मुद्रा-स्फीति को प्रभावी ढंग से नियंत्रण में रखने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है।

6. हाल ही में के वर्षों में आर्थिक कार्य निष्पादन का एक बूझा उत्साहपूर्ण लक्षण, औद्योगिक क्षेत्र में मन प्रगति व आधारभूत ढाँचे के क्षेत्र में सुधरा हुआ कार्य निष्पादन है। लगातार पिछले चार वर्षों में, विनिर्माण क्षेत्र में 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की दर से वृद्धि हुई है जिससे सरकार की औद्योगिक नीति की पुष्टि होती है। उद्योग के क्षेत्र में आशावादी लक्षण विद्यमान हैं जो निगमित क्षेत्र के सामान्यतः अच्छे कार्य निष्पादन और पूँजी बाजार में वृद्धिकारी स्थितियों में परिलक्षित है। बिजली के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है और तापीय संयंत्रों में संयंत्र भार अनुपात, जो 1984-85 में 50.1 प्रतिशत था, वह 1987-88 में बढ़कर 56.5 प्रतिशत हो गया। सान्नी योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए सृजन क्षमता के संबंध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। रेलों द्वारा होयी गई माल की मात्रा में सान्नी योजना के प्रथम तीन वर्षों में जो वृद्धि हुई है वह पिछले 10 वर्षों की अवधि में हुई कुल वृद्धि के बराबर है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन वर्षों के दौरान उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि हुई है। एक विशेष रूप से स्वागतयोग्य बात बुनियादी सामग्री वाले उद्योगों के कार्य निष्पादन में सुधार होना है। इस वर्ष के पहले 9 महीनों में, पिछले वर्ष की तदनुसृत अवधि के मुकाबले, एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा बिक्रीयोग्य इस्पात के उत्पादन में 10.1 प्रतिशत, सीमेंट के उत्पादन में 12 प्रतिशत, नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में 26.2 प्रतिशत और फास्फेटी उर्वरकों के उत्पादन में 64.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

7. केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है। इस वर्ष के प्रथम छः महीनों में 179 कार्यचालन उद्यमों के अस्थाई परिणामों से पता चलता है कि 1987-88 की तदनुसृत अवधि में हुआ 59.79 करोड़ रुपए का उनका निवल लाभ बढ़कर इस वर्ष 694.19 करोड़ रुपए हो गया है।

8. हम अपने सरकारी क्षेत्र के विकास को समर्थन प्रदान करने की नीति के प्रति बचनबद्ध हैं। किन्तु इस बात को मानते हैं कि कार्य निष्पादन का उच्चतर स्तर सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से संसाधन निर्माण के क्षेत्र में, कुछ परिवर्तन आवश्यक है। उनके दायित्वों के अनुरूप सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर रही है। सहमति ज्ञापन में, कतिपय वास्तविक, वित्तीय और संसाधन निर्माण सहित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में उद्यमों की जिम्मेदारियों तथा सरकार की ओर से, उद्यमों के लिए निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति को समर्थन प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। वर्ष 1988-89 के लिए सरकारी क्षेत्र के ग्यारह उपक्रमों ने सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 1989-90 के लिए सरकारी क्षेत्र के सात और उपक्रम सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर देंगे। सहमति

ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कम्पनियों के कार्य निष्पादन तथा सहमति ज्ञापन के अन्तर्गत अपना दायित्व पूरा करने में प्रशासनिक मंत्रालयों के काम का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

9. मैंने अर्थ-व्यवस्था में लचीलेपन तथा उद्योग और आधारभूत ढांचे में मुधरी हुई प्रगति का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि यही वह शक्ति है जिससे हम गरीबों के रहन-सहन स्तरों को सुधारने के अपने बुनियादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक तेजी से कार्य करने तथा अपने देश की आर्थिक स्वायत्तता को मजबूत करने की दिशा में काम कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा यदि सदन का ध्यान कतिपय समस्याग्रस्त क्षेत्रों की ओर भी आकर्षित न करूं।

10. एक क्षेत्र जिस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है वह है बचतों का प्रोत्साहन देना तथा बजटीय घाटे को नियंत्रण में रखना। हमें एक ऐसा राष्ट्र होने का सदा ही गर्व रहा है जहां बचत वर ऊंची रही है और हमारा संस्कृति में सदा ही सादे जीवन और मित्रव्ययिता के मूल्यों पर जोर दिया गया है। बजटीय नीति में बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस उपायों तथा विलासिता की वस्तुओं की खपत पर नियंत्रण लगाने के उपायों के जरिए इन मूल्यों पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए। इस दिशा में हमारा प्रस्ताव जो विशिष्ट उपाय करने का है, उनके संबंध में मैं अपने भाषण में बाद में जिक्र करूंगा।

11. उतनी ही महत्वपूर्ण, बल्कि कुछ अर्थों में उससे भी ज्यादा जरूरी बात तो यह है कि सरकारी व्यय की व्यवस्था मूखबुद्ध से की जानी चाहिए। कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि यह सरकारी व्यय जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, सरकारी कर्मचारियों के वेतनों और उनकी मजदूरी पर और सरकारी विभागों द्वारा अपना कारोबार चलाने के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय ही होता है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि रक्षा और सरकारी प्रशासन पर होने वाला केन्द्रीय सरकार का प्रत्यक्ष खपत व्यय कुल व्यय के एक चौथाई भाग से भी कम ही है। बजट के दसवें हिस्से से भी कुछ कम राशि केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय के लिए होती है। बजट व्यय का दो तिहाई भाग वस्तुतः व्यय करने वाले अन्य निकायों को, व्याज, आर्थिक सहायता, अनुदानों और ऋणों आदि के माध्यम से वित्तीय अन्तरणों के रूप में होता है। वास्तव में, जिस राशि की बजट में व्यय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उस राशि का एक बड़ा भाग लेखिक व्यवस्था के रूप में रखा जाता है, जिसे एक ओर पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में और दूसरी तरफ ऋणों और सामान्य शेयरों से किए जाने वाले निवेश के रूप में व्यय के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

12. मैं केन्द्रीय बजट के व्यय पक्ष की व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि यह बात साफ हो जाए कि व्यय के विषय में मूखबुद्ध बरतने को बात केवल कर्मचारियों, यात्राओं अथवा खरीदारियों के संबंध में किरायात करने के उद्देश्य से जारी किए गए अनुदेशों का पालन करने की कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है। यह अवश्य ही जरूरी बात है। इसके साथ-साथ व्यय को अन्य मदों, अर्थात् आर्थिक सहायता, अनुदानों और ऋणों जैसी मदों पर भी विचार करना केवल जरूरी ही नहीं बल्कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन में से अधिकतर मदें विनिर्दिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों में विन्यास हो चुकी हैं। हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि क्या हम आर्थिक सहायता को इन मदों, इन योजनाओं और कार्यक्रमों से भौतिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से मामलों में, हम वांछित परिणामों को, पहले से बेहतर लक्ष्य निर्धारित करके, अनेक कार्यक्रमों को समेकित करके, स्थानीय साधन जुटाकर उनका अधिक विकेन्द्रीयकरण करके और तुलनात्मक दृष्टि से कम लागत खर्च करके भी हासिल कर सकते हैं। अतः हम इस आशय को सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे कि ऐसा मूल्यांकन ही उन योजनाओं/कार्यक्रमों का आधार बने जो आठवीं आयोजना में शामिल किए जाएंगे।

13. भुगतान शेष का क्षेत्र बिना पैश करने वाला दूसरा क्षेत्र है। ऐसी हालत में जबकि पूंजी के निवेश और आधुनिकीकरण की अविनम्वनीय आवश्यकताएं हमारे सामने उपस्थित हों जिनके लिए आयात में वृद्धि करना बहुत ही आवश्यक हो, वैदेशिक भुगतानों की स्थिति पर कुछ हद तक दबाव अपहिय है। इसी वजह से सरकार ने, अर्थ-व्यवस्था के लिए आवश्यक आयातित वस्तुओं के मूल्य का भुगतान करने के लिए निर्यात में वृद्धि करने के उपायों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। इस दिशा में हमारी नीतियां बहुत मजबूत रही हैं और पिछले दो वर्षों में हमारे निर्यात में काफी तेजी से वृद्धि हुई है -- अर्थात् वर्ष 1987-88 में 25 प्रतिशत से ज्यादा और चालू वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में 24 से 25 प्रतिशत के बीच। लेकिन इसके साथ ही आयात के मूल्य में भी तेजी से वृद्धि हुई है, खासतौर पर ऐसी वृद्धि इस वर्ष की पहली छमाही में अधिक हुई है। आयात के क्षेत्र में यह वृद्धि, अंशतः खाद्यान्नों और खाद्य तेलों के आयात के कारण, जो कि पिछले वर्ष के सूखे की स्थिति के कारण आवश्यक हुआ और अंशतः धातुओं, रासायनिक पदार्थों और खाद्य तेलों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के कारण हुई है। इसके अलावा, ऋण की वापसी अशायगी का हमारा दायित्व भी अपेक्षाकृत ज्यादा रहा है। रिवायती शर्तों पर वित्त की सीमित उपलब्धि होने के कारण हमें विवश होकर वाणिज्यिक उधार का अधिक आश्रय लेना पड़ा है। किन्तु हमने उधारों को उतनी ही मात्रा में सीमित रखने का प्रयास किया है, जो हमारे बश से बाहर न हो।

वैदेशिक ऋणों के शोधन की व्यवस्था करने में हमें कठिनाई नजर नहीं आती।

14. भारतीय अर्थ-व्यवस्था सक्षम और सामर्थ्य सम्पन्न है। औद्योगिक क्षेत्र की सतत वृद्धि से और आधुनिकीकरण तथा स्तरवर्धन के कार्यों में किए गए पूजी निवेश से निर्यातों में वृद्धि का सद्परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। वस्तुतः भुगतान शेष की समस्या का ठीक समाधान भी यही है। मुझे पूरी आशा है कि निर्यात की वृद्धि की गति न केवल बराबर कायम रहेगी बल्कि इसमें वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर हमें कतिपय क्षेत्रों में कुछ हद तक घरेलू उपभोग पर अकुशल लगाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए ताकि निर्यात के लिए माल उपलब्ध किया जा सके।

15. व्यापक आधार पर आयात के लिए लाइसेंस प्रणाली के जरिए तदर्थ आयात विनियमन के माध्यम से भुगतान-शेष की अल्पावधिक कठिनाइयों को दूर करने के प्रलोभन से अभी हम बचे रहे हैं। ऐसी व्यवस्था अपने पाव पर स्वयं आघात करने के समान होगी, क्योंकि इससे अर्थ-व्यवस्था को आघात पहुंचेगा, निर्यात की वृद्धि रुक जाएगी और उद्योगों के आधुनिकीकरण के हमारे प्रयास कमजोर पड़ जाएंगे। नव दशक में हमारे आयात के स्वरूप और गठन में भारी परिवर्तन हुआ है। वर्ष 1980-81 में हमारे कुल आयातों में से 65 प्रतिशत भुगतान, कुछ थोक वस्तुओं अर्थात् खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, उर्वरकों और पेट्रोलियम तथा धातुओं के आयात के लिए करना पड़ता था, जबकि विदेशी मुद्रा के आबंटनों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में आयात का विनियमन करना अपेक्षित या आसान है। वर्ष 1987-88 में इन थोक वस्तुओं का आयात मूल्य कुल आयात मूल्य के केवल 33 प्रतिशत के बराबर था। अन्य आयातों के अन्तर्गत, विविध प्रकार की कच्ची सामग्री, पूंजीगत वस्तुएं, रासायनिक पदार्थ और औद्योगिक मघटक भी शामिल हैं। विदेशी मुद्रा आवंटनों के माध्यम से इनका प्रत्यक्ष विनियमन करना कठिन है। इससे विलम्ब और अकार्यकुशलता पैदा हो सकती है। इस लिए थोक-भिन्न आयात के मूल्य की अदायगी की व्यवस्था, अपरोक्ष साधनों का पहले से ज्यादा कारगर प्रयोग करके करनी होगी।

16. इस भाषण में, बाव में, मैं ऐसी कम प्राथमिकता वाली वस्तुओं के आयात का निरुत्साहित करने के कतिपय उपाय आपके समक्ष रखूंगा, जिनका उपभोग ऊंची आय के वर्गों के द्वारा किया जाता है। सफरी सामान-बंदी सभ्यता पर आधारित उपभोग को बढ़ावा देना हमारी औद्योगिक और व्यापारिक नीति का उद्देश्य नहीं है। इस प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाना चाहिए।

17. ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जिनका आयातित वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग किया जा सके, औद्योगिक नीति को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण

भूमिका निभानी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सरकार इस आशय की सुनिश्चित व्यवस्था करेगी कि विदेशों से भारी मात्रा में मगवाई जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आने वाली स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि की जाए और इस व्यवस्था में जो व्यवधान उपस्थित हो उन पर पुनर्विचार करके दूर कर दिया जाए।

18. अब मैं उन क्षेत्रों का उल्लेख करूंगा, जिन पर इस बजट में विशेष रूप से ज़रूर दिया गया है।

गरीबी दूर करने के कार्यक्रम

19. उत्तरोत्तर बजटों के माध्यम से गरीबी और बेरोजगारी की बुनियादी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप में दूर करने के प्रयास किए जाते रहे हैं और वर्ष 1980-81 के बाद से इन प्रयासों में पहले से ज्यादा वृद्धि हुई है। ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवाओं और खाद्य तथा वस्त्रों सम्बन्धी आर्थिक सहायता पर उस वर्ष केन्द्रीय बजट के अनुसार 1,971 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय हुआ। इन क्षेत्रों में अधिकतर व्यय की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से ऐसे लक्ष्यबद्ध कार्यक्रमों के लिए है, जो गरीबी, अनुसूचित जातियों और जन-जातियों जैसे समाज के कमजोर और निर्बल वर्गों को रोजगार प्रदान करने और उनकी आयोपार्जक क्षमता में वृद्धि करने, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख और जलपूर्ति जैसे बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने और अनिवार्य उपभोग की कतिपय मद्दों के सबध में आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार किए गए हैं। वर्ष 1988-89 में बजट अनुमानों में ऐसे कार्यों के लिए 8,652 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

20. मैंने इस कुल व्यय में कृषि और उर्वरकों सबधी आर्थिक सहायता के उस व्यय को शामिल नहीं किया है, जो वास्तविक रूप में वर्ष 1980-81 में 1,179 करोड़ रुपये था और वर्ष 1988-89 की बजट व्यवस्था में बढ़ कर 4,343 करोड़ रुपये हो गया।

21. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 250 लाख से अधिक परिवारों को आमदनी देने वाले काम धंधे करने के लिए सहायता दी गई है। छोटी आयोजना के प्रारम्भ से, इस कार्यक्रम पर कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है, जिसमें विस्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध किए गए सावधिक ऋण भी शामिल है।

22. माननीय सदस्यों को यह सूचना देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ग्रामीण निर्धनों के लिए रोजगार पैदा करने वाले दो कार्यक्रमों, अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के जरिए वर्ष 1987-88 के दौरान 67 करोड़ जनविवसों का रोजगार पैदा किया गया जबकि लक्ष्य 50 करोड़ जनविवसों का रोजगार पैदा करने का था।

23. स्वरोजगार और मजूरी रोजगार के मौजूदा मुख्य कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण निर्धनता की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रहार करके उसे दूर करने की हमारी वर्तमान नीति जारी रहेगी और कम लागत में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जाएंगे।

24. रोजगार हमारी जनता की सबसे बड़ी तात्कालिक आवश्यकता है। रोजगार में यह वृद्धि मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में होने वाली वृद्धि में और श्रमिक-बहुल कृषि संसाधन उद्योगों तथा सेवाओं की व्यवस्था का विकास करके ही होगी। किन्तु बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए उस पर प्रत्यक्ष प्रहार करना अत्यावश्यक है। इसलिए रोजगार पैदा करने में समग्र कार्यक्रमों के लिए हम विशेष प्राथमिकता निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम इन दोनों को एक ही सूत्र में पिरो देने का प्रस्ताव है और हम यह चाहते हैं कि इनका कार्यान्वयन विकेन्द्रीयकृत ढंग में किया जाना चाहिए। एक सूत्र में आबद्ध हम कार्यक्रम का समूचे देश में कार्यान्वित किया जाएगा और उस पर होने वाले 75 प्रतिशत व्यय की वित्त-व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाएगी।

25. कुछ अनुविधाप्राप्त क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है और विद्यमान रोजगार कार्यक्रम उन आवश्यकताओं से कम हैं। इसलिए पुनर्गठित राष्ट्रीय कार्यक्रम के अतिरिक्त एक नया गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत उन 120 चुने हुए जिलों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा जो पिछड़े हुए हैं और जहाँ बहुत ज्यादा बेरोजगारी है।

26. इस वर्ष अथवा हम आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मना रहे हैं उस पुण्यात्मा को स्मरण करने का इससे बेहतर दूसरा तरीका शायद ही कोई है कि गरीबी और बेरोजगारी का दूर करने के लिए हम अपनी कोशिशों का और तेज करें। यह कार्यक्रम उसी दिशा में अग्रसर होने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम का नामकरण भी पंडितजी के नाम पर होगा जो हमारे देशवासियों का उनके प्रति अत्यंत स्नेह का परिचायक है।

27. इस नए कार्यक्रम में, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। इस स्कीम के लिए दिया जाने वाला धन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिले के लिए उपलब्ध व्यवस्था के अलावा होगा। इन निधियों को मिला दिया जाएगा और रोजगार अवसरों को अधिकतम बनाने के लिए तथा उत्पादक सम्पत्तियों के सृजन के लिए स्थानीय रूप से उपयोगी स्कीम शुरू

की जाएंगी। हमें उम्मीद है कि इस नई स्कीम के जरिए रोजगार के लिए व्यवस्था में वृद्धि करने में निर्धनों के रहन-सहन स्तरों में पर्याप्त सुधार और इन क्षेत्रों में उत्पादक तथा सामाजिक रूप से उपयोगी सम्पत्तियों में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। इस कार्यक्रम के व्यय की घोषणा बाद में की जाएगी। वर्ष 1989-90 में इस नए कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था को शामिल करके वर्ष 1989-90 में रोजगार कार्यक्रम के लिए 1,711 करोड़ रुपए की व्यवस्था होगी। इस नए कार्यक्रम को लागत का पूरा करने के लिए मेरा प्रस्ताव मूलतः उन लोगों में अतिरिक्त साधन जुटाने का है जिनको पहले ही पर्याप्त आय है और जिन्हें लाभप्रद रोजगार के लाभ प्राप्त हैं। मैं इसके संबंध में अपने भाषण में पुनः उल्लेख करूंगा।

28. इस दिशा में राज्य सरकारों द्वारा किए गए और प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हाल ही में संविधान में संशोधन करके व्यवसाय कर को अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। हम राज्य सरकारों से यह आग्रह करते हैं कि वे इस समर्थकारी प्रावधान का उपयोग रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए करें।

29. अधिक रोजगार की व्यवस्था गरीब घरानों का अपने जीवनयापन के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद देगी। इसके साथ महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार करने के लिए पहले से अधिक प्रयत्न प्रयास को आवश्यक भी हैं। इसलिए मैं साधनहीन महिलाओं की साढ़ियों का मुफ्त वितरण किए जाने के नए कार्यक्रम का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ। जहाँ तक बच्चों का सम्बन्ध है, पहले चल रहे एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम में काफी ज्यादा विस्तार किया जाएगा और इस कार्यक्रम को पहले से इसके अन्तर्गत लिए गए 1700 खण्डों के अलावा 500 और अधिक खण्डों में भी शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब बच्चों के स्वास्थ्य, पोषाहार और शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाना है।

30. इस वजह से ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवाओं तथा खाद्य और कपड़े के संबंध में आर्थिक सहायता के लिए 9,374 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है।

31. गरीबी-विरोधी तथा सामाजिक सेवा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मुख्यतः राज्यों की प्रायोजनाओं के जरिए होता है। इनमें से बहुत से कार्यक्रमों के लिए विदेशों से सहायता प्राप्त होती है। इस समय, विदेशों से सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त सहायता का 70 प्रतिशत राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। इस व्यवस्था से संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि राज्यों को उल्लेख कराई जाने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को बढ़ाकर सामाजिक सेवा क्षेत्रों में विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं तथा निर्धनता

उन्मूलन पर प्रत्यक्षतः प्रभाव डालने वाले कार्यक्रमों के लिए प्राप्त सहायता के 100 प्रतिशत के बराबर किया जा सके। इस निर्णय से, राज्यों को वर्तमान प्रबंधों के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी और उन्हें इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अतिरिक्त निवेश करने में सुविधा होगी। इस निर्णय से जिन क्षेत्रों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है वे हैं: कृषि ग्रामीण विकास, सिंचाई, पर्यावरण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण, महिला विकास, शिक्षा, आवास, जलपूर्ति और शहरी विकास।

कृषि

32. कृषि हमारी जनसंख्या का मुख्य आधार है और हमारी योजनाओं में इस क्षेत्र को प्राथमिकता प्राप्त है। इस समय कृषि उत्पादों और निविष्टियों पर करों का बोझ न्यूनतम है और वस्तुतः केन्द्रीय और राज्यों के बजटों में भारी आर्थिक सहायता दी जाती है।

33. जैसा कि मैंने पहले कहा है, 1980-81 के बाद से, कृषि तथा उर्वरक सहायता पर आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वर्ष भी इस व्यवस्था में वृद्धि की जा रही है और यह खर्चा 5,173 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच जाएगा।

34. कृषि उत्पादन के लिए ऋण एक मुख्य निविष्टि है। कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की प्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था करने के लक्ष्य को, जिसका पिछले वर्ष उन बैंकों के कुल बकाया अग्रिम के 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया था, और आगे बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया जा रहा है और इस पर वर्ष 1989-90 के अंत तक अमल कर लिए जाने का लक्ष्य है। इस अभिवृद्धि के पश्चात्, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को उपलब्ध किए जाने वाले कुल ऋण की मात्रा में वर्ष 1989-90 में 4,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की वृद्धि होगी। माननीय सदस्यों का इस बात की जानकारी है कि कि 15,000 रुपये तक के फसल संबंधी ऋणों के ब्याज की दर पिछले वर्ष कम कर दी गई थी और यह कमी 1 प्रतिशत से लेकर 2½ प्रतिशत के बीच थी। राशन की गुंजाइश को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक आज 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक के फसल संबंधी ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर का 14 प्रतिशत की मौजूदा अधिकतम दर से घटाकर 12 प्रतिशत करने के लिए अनुदेश जारी कर रहा है।

35. राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति एक चिन्ता का विषय है। इसके अतिरिक्त सिंचाई की निर्मित क्षमता तथा उपयोग के बीच कमी को पूरा

करने के लिए काफी कुछ करने की गुंजाइश है। कृषि और सिंचाई के लिए बाह्य सहायता को अधिक उपलब्धता की व्यवस्था करने के निर्णय में, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, राज्य आयोजनाओं में इन प्रयोजनों के लिए उपलब्ध निधियों में वृद्धि हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इससे सहायता निधियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने में मदद मिलेगी।

36. हमारी ग्रामीण प्रयोजनात्मकता में आमदनी में तेजी में वृद्धि होने से न केवल अधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी बल्कि इसके लिए फसलों के विविधिकरण, बेहतर फसल-कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादों की उच्च कीमत वाले उत्पादों में संसाधित करने आदि की भी आवश्यकता होगी।

37. किसानों और उद्योग के बीच एक गतिशील संबंध कायम करने के उद्देश्य से, ताकि कृषि उत्पादों का बेहतर उपयोग हो सके, ग्रामीण उत्पाद के मूल्य में अधिक वृद्धि हो सके, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विपुल अवसर प्राप्त हो सके, ग्रामीण आय के निचले स्तर में वृद्धि हो सके और खाद्य संसाधन में आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश किया जा सके, खाद्य संसाधन उद्योग नामक एक नया मंत्रालय जुलाई, 1988 में गठित किया गया था, जो विकासशील देशों में अपने किस्म का पहला मंत्रालय है। इस मंत्रालय का एक अन्य उद्देश्य उन अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है जो फलों और सब्जियों की कटाई से पहले और बाद में बड़े पैमाने पर व्यर्थ जाते हैं, और इस प्रकार उत्पादित खाद्य पदार्थों की आर्थिक उपयोगिता में सुधार करना और लोगों के लिए उपलब्ध पोषणात्मक निविष्टियों में वृद्धि करना भी है। बाद में मैं अपने भाषण में इन उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ राजकोपीय प्रोत्साहनों का उल्लेख करूंगा।

आवास

38. सरकार आवास को बहुत ऊंची प्राथमिकता देती है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे अत्यंत आवश्यक जरूरत पूरी होती है और जिससे बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इस उद्देश्य के अनुसरण में सरकार ने एक बहुत 'राष्ट्रीय आवास नीति तयार की है। आवास वित्त के क्षेत्र में 1988-89 में बहुत से नए उपाय किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास ऋण संबंधी शर्तों को उदार बना दिया है। जीवन बीमा निगम ने 'बीमा निवास योजना' नामक एक नई स्कीम शुरू की है जिससे पालिसी धारकों को फलनों के निर्माण अथवा खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

39. 'राष्ट्रीय आवास बैंक' की स्थापना की गई है और इसने काम करना शुरू कर दिया है। एक स्वस्थ आवास वित्त प्रणाली को प्रोत्साहित करना और आवास क्षेत्र के लिए

पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करना इस बैंक के प्रमुख कार्य है। अपनी वित्त नीतियाँ तैयार करने समय बैंक गरीब आदमी को पहुँचे के उद्देश्य का पालन करेगा। तदनुसार बैंक ने 40 वर्ग मीटर तक के कम आय वाले आवास के लिए दिए गए ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त की स्कीम की घोषणा की है। इसी प्रकार, भूमि विकास तथा इसके द्वारा वित्त पोषित आवास परियोजनाओं के संबंध में बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि इन प्रकार विकसित किए जाने वाले प्लॉट अथवा निर्मित किए जाने वाले मकानों का 75 प्रतिशत उन लोगों के लिए हो जो 40 वर्ग मीटर तक का निर्मित आवास प्राप्त करने के के इच्छुक है।

40. अपना मकान बनाने की आशा, बचत के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। इसलिए हमने 'गृह ऋण खाता स्कीम' नामक एक नई स्कीम शुरू करने का निर्णय किया है जिसे अनुसूचित बैंकों के सहयोग से राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा शुरू किया जाएगा। समाज के, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के, सभी वर्गों के लोगों द्वारा इसमें भाग लेने को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि में, इस बचत स्कीम के लिए 30 रुपये प्रति मास अथवा 360 रुपये प्रति वर्ष का न्यूनतम अंशदान निर्धारित किया गया है। बचतों पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति, जिसका कहीं भी कोई मकान नहीं है, इस स्कीम में शामिल होने का पात्र होगा। न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि तक बचत करने पर एक सदस्य को संवर्धित बचतों, जिसमें ब्याज भी शामिल होगा, के गुणकों की राशि तक के बराबर ऋण मिल सकेगा। 'गृह ऋण खाता स्कीम' को सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा भूमि अथवा मकानों के आवंटन के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इन बचतों के संबंध में मैं कुछ रियायत देने का प्रस्ताव करूंगा।

औद्योगिक विकास

41. अब मैं औद्योगिक क्षेत्र के बारे में कुछ कहूंगा। उद्योगों और आधारभूत क्षेत्र के सकल कार्य निष्पादन का उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूँ। हमें विश्वास है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग, मूल्यों और संवितरण नियंत्रणों तथा व्यापार नीति के संबंध में जो परिवर्तन हमने पिछले कुछ एक वर्षों में किए हैं, उनमें हमें बहुत फायदा पहुँचा है। नीति विषयक इन परिवर्तनों का उछेस पतियोगितात्मक सक्षमता को बढ़ाकर औद्योगिकी के अग्रग्रहण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देकर, विकास और कुशलता दोनों ही को प्रोत्साहन प्रदान करना रहा है। आज हमारा औद्योगिक ढांचा बहुत जटिल बन चुका है। इसके बहुत से अवयव परिपक्वता की निश्चित अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। इस स्थिति में, हमारे लिए यह संभव है कि हम विस्तृत विनियमों में ढील देकर भी, राजकोपीय और ऋण संबंधी नीतियों का अविन्यपूर्ण उपयोग करके, विकास की दिशा का नियंत्रण कर सकने में समर्थ हो सकें। इसी पद्धति का अनुसरण करके सरकार ने सीमेंट और एल्युमिनियम के मूल्य और संवितरण पर से तत्काल नियंत्रण हटा देने का फैसला किया है।

42. दिनांक 28 फरवरी, 1982 में सीमेंट पर से आंशिक रूप से नियंत्रण हटा दिए जाने के बाद से सीमेंट उद्योग के उत्पादन में प्रभावोत्पादक वृद्धि हुई है। अनुमान है कि सीमेंट का उत्पादन, जो वर्ष 1981-82 में 210.1 लाख मीट्रिक टन था, वर्ष 1988-89 में बढ़कर 435 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 1989-90 में और बढ़कर 490 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा। इस अवधि में लेवी दायित्व में भी उत्तरोत्तर कमी हुई है और लेवी सीमेंट के लिए मुनासिब सस्ती कीमत रखी गई है। इन नीतियों के अनुसरण के कारण वर्ष 1985 से सीमेंट का आयात समाप्त हो गया है। वस्तुतः इस समय देश सीमेंट का निर्यात कर सकने की स्थिति में आ पहुँचा है। हमारी दीर्घवधिक नीति के अनुसार हम आठवी योजना के अन्त तक सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाकर 650 लाख मीट्रिक टन और नवीं आयोजना के अन्त तक 870 लाख मीट्रिक टन करना चाहते हैं। इस समय, लेवी का दायित्व उद्योग के समग्र उत्पादन के 20 प्रतिशत से भी कम ही बैठता है। इसलिए अब यह फैसला किया गया है कि सीमेंट उद्योग पर लगे मूल्यों और संवितरण संबंधी सभी नियंत्रणों को पहली मार्च, 1989 से समाप्त कर दिया जाए। देश के दूरस्थ और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के उचित कीमतों पर सीमेंट की उपलब्धता की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए आर्थिक सहायता की एक उपयुक्त योजना भी तैयार की जा रही है।

43. राष्ट्रीय एल्युमिनियम कम्पनी (नालको) के उत्तरोत्तर चालू होने से भारत ने एल्युमिनियम धातु के उत्पादन में बहुत तरक्की की है। वर्ष 1987-88 में 2,78,000 मी. टन का रिकार्ड उत्पादन प्राप्त करने के बाद, वर्ष 1988-89 में उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि होने और यह लगभग 3,60,000 मी. टन होने का अनुमान है। वर्ष 1989-90 के दौरान एल्युमिनियम के उत्पादन में 20 प्रतिशत की और वृद्धि होने तथा यह 4,50,000 मी. टन के स्तर तक पहुँच जाने की उम्मीद है। नालको और एल्युमिनियम तथा कुछ एल्युमिनियम भी निर्यात कर रहा है और वर्ष 1988-89 के दौरान यह लगभग 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जन करेगा। इस प्रकार भारत एल्युमिनियम धातु के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि आने वाले वर्षों में यह निर्यात योग्य अधिशेष का भी उत्पादन करेगा। इस बात को देखते हुए सरकार ने 1.3.1989 से एल्युमिनियम की कीमत और वितरण पर से नियंत्रण हटाने का निर्णय किया है।

44. पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना हमारी औद्योगिक नीति का मुख्य आधार है। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में मुख्य बाधा आधारभूत ढाँचे का अभाव है। हाव ही से सरकार ने विकास केन्द्र स्कीम के रूप में इस संबंध में एक नए दृष्टिकोण की घोषणा की है। प्रथम चरण के अन्तर्गत 61 विकास केन्द्रों को चुना जाएगा और वहाँ उच्च कोटि की आधारभूत सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। सन् वर्ष 1985-90 की आयोजना में इस स्कीम के लिए

20 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंशदान की व्यवस्था की है और इसके कार्यान्वयन की गति को ध्यान में रखते हुए, यदि आवश्यक हुआ तो इसमें और वृद्धि की जाएगी।

45. अब मैं पूँजी बाजार के बारे में कहना चाहूँगा। वैयक्तिक बचतों की एक बहुत बड़ी मात्रा इन बाजार में किए जाने वाले वित्तीय साधनों के कारोबार के जरिए लगाई जाती है। वस्तुतः हमारी वित्तीय प्रणाली की दृढ़ता और विस्तार एक सम्पत्ति है और हमें इसका उपयोग बचतें जुटाने और उन्हें उत्पादक साधनों में लगाने के लिए करना चाहिए। हमारे ग्रामीण लोग बांडों, ऋण-पत्रों और शेयरों के रूप में निवेश करने में अधिक रुचि लेने लगे हैं। तथापि, स्रोत पर कर की वटंती इसमें उत्साह को कम करती है। हमने लाभार्थों के मामले में निचली सीमा को बढ़ाकर पहले ही 2,500 रुपए कर दिया है जिस पर स्रोत पर कटौती नहीं की जाएगी। बांडों और ऋण-पत्रों पर ब्याज की अदायगियों के सम्बन्ध में भी मेरा यही करने का प्रस्ताव है।

46. पूँजी बाजार में बचतों का निवेश बहुत हद तक निश्चित ब्याज वाले बांडों और ऋण-पत्रों तक सीमित है। किन्तु, औद्योगिक विकास के लिए इक्विटी के रूप में जोखिम पूँजी भी आवश्यक है। वैयक्तिक बचतों को इक्विटी में निवेश करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार का इरादा एक 'इक्विटी संयोजित बचत स्कीम' शुरू करने का है। यह स्कीम यू.टी.आई. और मान्य सांझी निधियों के माध्यम से संचालित की जाएगी और इसमें किए गए निवेशों को, ऐसी बचतों में होने वाली निवल वार्षिक वृद्धि के आधार पर कर संबंधी कटौती की सुविधा की पात्रता प्राप्त होगी। स्कीम के ब्यौरे की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी।

47. औद्योगिक क्षेत्र में जो गतिशीलता आई है वह काफी हद तक हमारे द्वारा प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। तथापि, जैसे-जैसे औद्योगिक पर्यावरण अधिक प्रतियोगी बना जाएगा, वैसे-वैसे हमें औद्योगिक रणनीति को साक्षात्कार में निपटने के लिए प्रभावी उपाय करने आवश्यक होंगे। रणनीति औद्योगिक कम्पनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत कुछ प्रबन्ध मौजूद है, तथापि, यह आवश्यक है कि सक्षम रणनीति इकायों को अपना पुनरुत्थान स्वयं करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करने के वास्ते कदम उठाए जाएं ताकि रणनीति की स्थिति हो न आए। इस दृष्टि से, सरकार का इरादा कर्मजोड़ इलाहियों के लिए एक उत्पाद शुल्क राहत स्कीम तैयार करने का है जिससे कि निर्धारित वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित विविधीकरण आधुनिकीकरण, अथवा पुनरुत्थान पैकेज के एक भाग के रूप में उचित उत्पाद शुल्क अदायगियों का एक अनुपात उपलब्ध कराया जा सके।

अन्य क्षेत्र

48. अब मैं उन कुछ अन्य क्षेत्रों का जिक्र करूँगा जिनके संबंध में मेरा कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।

49. सरकार, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम की इस दृष्टि से जांच कर रही है कि क्या इसमें अपना प्रयोजन सिद्ध किया है या नहीं और क्या इसमें किसी संशोधन की जरूरत है। इस जांच को ध्यान में रखते हुए सरकार का प्रस्ताव स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि केवल प्राइमरी स्वर्ण पर कुछ नियंत्रण रखा जा सके। इससे हज़ारों स्वर्णकारों और दस्तकारों को लाभ होगा जो अपने पुराने परम्परागत व्यवसाय को मुक्त रूप से चला सकेंगे और अपने ग्राहकों को गुणवत्ता, शुद्धता और कीमत की दृष्टि से बेहतर सेवा प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा इससे स्वर्ण आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा जो स्थिर बना हुआ है। ब्यौरे तैयार किए जाएंगे और शीघ्र ही आवश्यक विधान पेश किया जाएगा।

50. मैंने बचतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता का जिक्र किया था और इस प्रयोजन के लिए दो उपायों का पहले ही उल्लेख किया है — 'गृह ऋण खाता स्कीम' और 'इक्विटी संयोजित बचत स्कीम' हाल ही के वर्षों में अन्य बचतों के संबंध में बहुत से उपाय किए गए हैं। मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 1986 में शुरू किए गए इंदिरा विकास पत्र और वर्ष 1988 में शुरू किए गए किसान विकास पत्र काफी मात्रा में बचतों को आकर्षित कर रहे हैं। इन दो बचत पत्रों के संबंध में कोई कर रियायत उपलब्ध नहीं है। मेरा प्रस्ताव एक नई राष्ट्रीय बचत पत्र श्रृंखला VIII शुरू करने का है जिस पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा और ये धारा 80ग के अंतर्गत कर रियायत के पात्र होंगे, न कि धारा 80ठ के अंतर्गत। विद्यमान राष्ट्रीय बचत पत्र श्रृंखला VI और VII को बन्द कर दिया जाएगा। यह बचत प्रोत्साहनों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया का एक भाग है।

51. मैं, भविष्य निधि में कामगारों की बचतों और उपदान (प्रेच्युटी) के अधिकार को सुरक्षित रखने की जरूरत के प्रति सजग हूँ। न्यूनतम अंशदान 8-1/3 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है और यह बढ़ी हुई दर 1-8-1988 से लागू हो गई है। उपदान देयता के अनिवार्य बीमा अथवा आयकर नियमों के अंतर्गत उपदान निधि स्थापित करने के लिए, जिसके संबंध में निवेश की पद्धति वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी, उपदान अदायगी अधिनियम संशोधित कर दिया गया है। आवश्यक नियम तैयार होते ही इन प्रावधानों को तुरन्त कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

52. जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं, सरकार ने पिछले कुछ समय में पेंशन भोगियों की सहायता करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने की इच्छुक है कि पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ की स्वीकृति और अदायगी तुरन्त कर दी जानी चाहिए और संवितरण की

प्रक्रिया सरल बना दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने सिविल पेशनरों को पेशन अदायगी की प्रक्रिया को और सरल बनाने तथा अपनी पेंशन बैंक से लेने के संबंध में निर्णय लिया है। प्रस्तावित सरलीकरण के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि महालेखाकार और जिला राजकोषों की दो मध्यवर्ती एजेंसियों को इस कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा, इसकी देख-रेख वित्त मंत्रालय में एक नए मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय (पेशन) द्वारा की जाएगी। पेशन अदायगी और उसके हिसाब-किताब में संशोधित सम्पूर्ण कार्य को कंप्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव है। नई प्रणाली को वर्ष 1989-90 के दौरान लागू करने का प्रभाव है।

53. मेरा प्रस्ताव मेवानियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए नई बचत स्कीम और परिवार पेशन के संबंध में कुछ राजकोषीय राहत प्रदान करने का भी है, जिसके संबंध में मैं बाद में उल्लेख करूंगा।

54. हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में महान बलिदान दिए हैं। इस वर्ष में जब कि हम स्वतंत्रता संघर्ष के एक महानतम सेनानी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, यह उचित ही होगा कि हम राष्ट्र द्वारा उनके प्रति व्यक्त की गई कृतज्ञता को मूर्त रूप देने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की पेशन बढ़ाकर 750 रुपए तक कर दें।

55. अग्रे मैं 1988-89 के संशोधित अनुमानों और 1989-90 के लिए बजट अनुमानों के बारे में कहना चाहूंगा।

संशोधित अनुमान, 1988-89

56. चालू वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करने के बाद से, खर्च में कुछ अनिवार्य वृद्धियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक हो गए हैं। केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता में 771 करोड़ रुपए की वृद्धि करनी पड़ी। वृद्धियां, मुख्यतः फसल बीमा स्कीम में उत्पन्न दावों के निपटान, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए सड़क, विद्युत वित्त निगम के इक्विट आधार को सुदृढ़ बनाने, पिछली नौवहन विकास निधि समिति द्वारा की गई बचतबख्ताओं को पूरा करने के लिए नौवहन कंपनियों को अदायगी और वित्तीय संस्थानों को प्रदान की गई विदेशी सहायता के बराबर रुपयों की अदायगी करने से संबंधित हैं।

57. राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता 421 करोड़ रुपए अधिक होने की आशा है जिसका मुख्य कारण पंजाब को उसके आयोजना परिषद के वित्तपोषण के लिए अदा की जाने वाली विशेष सहायता है।

58. आयोजना-भित्त मदों के अंतर्गत नियत संवर्धन और बाजार विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की जानी है। देशी उर्वरकों पर आर्थिक सहायता भी 250 करोड़ रुपए अधिक होगी। रक्षा खर्च में 200 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि की गई है। रक्षा पेंशनों में

संशोधन से उत्पन्न वास्तविक दावों के आधार पर रक्षा पेंशन-भोगियों के लिए 497 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता होगी। बाढ़ से प्रभावित राज्यों को अनुदान सहायता में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि करनी होगी। सुरक्षात्मक उपायों के कारण पंजाब में कुछ आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था पर 71 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

59. कुछ और वृद्धियां भी हुई हैं। इन सभी के कारण आयोजना-भित्त व्यय में और घाटे की स्थिति-व्यवस्था में कहीं अधिक वृद्धि होती। सरकार ने व्यय में वृद्धि को नियंत्रित करने तथा प्राप्तियों में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न में उपाय किए हैं।

60. मंत्रालयों और विभागों से कहा गया था कि वे व्यय में वृद्धि को जिसमें सरकारी कर्मचारियों की वर्ष के दौरान स्वीकृत बोनस और मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों की देयता शामिल है, यथासंभव अधिकतम सीमा तक पूरा करने के लिए बचनों का पना लगाएं। विछने वर्ष जारी किए गए मितव्ययिता संबंधी अनुदेशों को इस वर्ष भी जारी रखा गया। इन उपायों के फलस्वरूप आयोजना-भित्त व्यय को सीमित रखा जा सका है।

61. सकल कर राजस्व 776 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होने का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्यतः संघ उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और निगम कर में हुई है। करभित्त राजस्व के अंतर्गत, आयातित खाद्य तेलों में लाभ में काफी कमी होने की सम्भावना है जिसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमती में वृद्धि है। आशा है कि पूंजीगत प्राप्तियों ने पर्याप्त मुआवजा होगा। अब सरकार की कुल प्राप्तियां 67,843 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमानों में यह राशि 66,076 करोड़ रुपए थी। कुल व्यय 75,783 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमान 73,560 करोड़ रुपए का था। वर्ष का कुल घाटा अब 7,940 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस प्रकार, बजट पर पड़े अत्यधिक अतिरिक्त बोझ और दी गई बहुत सी रिश्वतों के बावजूद यह सुनिश्चित किया गया है कि संपन्न घाटे में अत्यधिक वृद्धि न हो।

वर्ष 1989-90 के लिए बजट अनुमान

62. अगले वर्ष, मातृवी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होने के कारण, यह सुनिश्चित करने का भरपूर प्रयास किया गया है कि विकास के लिए अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय मर्यादा की राशि, जिसमें नए आर्थिक कार्यक्रमों के लिए 500 करोड़ रुपए की विशेष अतिरिक्त व्यवस्था शामिल है, 16,964 करोड़ रुपए रखी गई है। केन्द्रीय आयोजना के लिए आन्तरिक तथा बजट बाह्य माधनों की राशि 17,482 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस प्रकार 1989-90 के लिए कुल केन्द्रीय आयोजना परिषद 34,446 करोड़ रुपए होगा जबकि चालू

वर्ष का अनुमोदित परिव्यय 28,715 करोड़ रुपए का है, जो लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि का स्रोतक है।

62. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पांच वर्षों की अवधि में केन्द्रीय क्षेत्र का वार्षिक परिव्यय का लगभग 115 प्रतिशत होगा।

64 वर्ष 1989-90 की केन्द्रीय परियोजना में, कृषि, ग्रामीण विकास और इनमें पंचांग क्षेत्रों पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। जनव्यय के अनुसार वर्गीकृत विभिन्न कृषि क्षेत्रों के आधार पर कृषि संबंधी आयोजन के लिए एक नवीन नीति प्रतिपादित की गई है। केन्द्रीय आयोजना के अन्तर्गत, कृषि और मिर्चाई संबंधी व्यवस्था को बढ़ाकर 1408 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मैं उर्वरक विभाग के लिए 495 करोड़ रुपए का आवंटन किए जाने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

65. ग्रामीण विकास के कार्यक्रम आयोजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं। इन नए कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्था सहित, केन्द्रीय आयोजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र के लिए जाने वाली कुल मिलाकर व्यवस्था में 28.4 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए, पुनर्गठित खादी ग्रामोद्योग आयोग के विविध दिशाओं में अपनी गति-विधियों का विस्तार करने की योजना बनाई है। प्रचलन वर्ष में संशोधन के प्रयोजन में निश्चित किए गए 33 नए उद्योगों के अलावा, भविष्य में 41 अन्य उद्योगों के विकास का काम भी विभिन्न चरणों में शुरू किया जाएगा।

66. केन्द्रीय आयोजना के अन्तर्गत सामाजिक सेवाओं के लिए व्यवस्था को बढ़ाकर 3396 करोड़ रुपए किया जा रहा है। वर्ष 1989-90 की वार्षिक आयोजना में, समाज कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्रारंभिक शिशु सुश्रूषा सेवाओं की व्यवस्था करने, महिलाओं के उद्धार, असमर्थताओं के निवारण और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था करने पर जोर दिया जाएगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, 1 कोटित शिशु विकास सेवा संबंधी कार्यक्रमों निर्धन और बेसहारा महिलाओं के लिए आमदनी पैदा करने वाली योजनाओं, शिक्षा और अपंग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक पुनरुद्धार के कार्यक्रमों में भारी विस्तार करने का विचार है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन पर किए गए अत्याचारों और बाल-विवाह, दहेज आदि क्रूरतियों तथा मादक पदार्थों आदि के विरुद्ध संघर्ष करने के संबंध में भी पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।

67. सातवीं आयोजना में मानव संसाधनों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। सातवीं पंचवर्षीय आयोजना सोद्देश्य पद्धति, उसकी नीतिमत्ता और उसमें सम्मिलित मुख्य विकासोपेक्षी के समुत्थान के कार्यक्रमों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को, जिनको 1977-88 तक कायम रखा गया है, आगे भी जारी

रखा जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने, प्रौढ निरक्षरता के उन्मूलन, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, उच्च-शिक्षा के स्तर और उसकी गुणवत्ता में सुधार और समेकित करने तथा त लोकी शिक्षा का आधुनिकीकरण करने और उसके अध्यक्षद्वारा विषयों को समाप्त करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

68. हाल ही के वर्षों में हुए विकास की गति को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने आंतर-भूत क्षेत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों में बराबर पंजी लगाने रहें। इसलिए केन्द्रीय आयोजना के अन्तर्गत, विद्युत-विकास के संबंध में की जाने वाली व्यवस्था में 38.6 प्रतिशत, रेलवे के लिए की जाने वाली व्यवस्था में 15.6 प्रतिशत और दूर-संचार के लिए की जाने वाली व्यवस्था में 56.6 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

69. सातवीं आयोजना में सम्मिलित औद्योगिक क्षेत्रों की मुख्य सरकारी परियोजनाओं को या तो पूरा कर लिया गया है या फिर आयोजना के अंतिम वर्ष तक उनकी पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिया जाएगा। इन परियोजनाओं में, भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में प्रथम चरण की संपूर्ण, उड़ीसा में नालको के एल्युमिनीयम कम्प्लेक्स, विजयपुर, आगरा और नामका 3 में गैस-आधारित उर्वरक संयंत्रों उद्योगमंजल के प्रौद्योगिक परियोजना, दुर्गापुर, बरीनी, पानीपत और भटिंडा के आबद्ध विजनी-चरां की और महाराष्ट्र गैस-क्रैकर कम्प्लेक्स की परियोजनाएं शामिल हैं।

70. औद्योगिक क्षेत्र में, वार्षिक आयोजना 1989-90 के अन्तर्गत, उत्पादक योजनाओं और सातवीं आयोजना के पिछले वर्ष में चालू की जाने वाली विकासोन्मुख परियोजनाओं के लिए आठवीं आयोजना के मध्य में आवश्यक प्रारंभिक कारवाई शुरू करने का उद्देश्य से पर्याप्त परिव्ययों की व्यवस्था कर दी गई है।

71. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 10,850 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि इनकी तुलना में चालू वर्ष में 9,714 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इस प्रकार आयोजना खाने के अन्तर्गत केन्द्रीय बजट में आने वाले कुल मिलाकर 27,814 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, जबकि चालू वर्ष के बजट में इस व्यय के लिए 25,714 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी।

72. सरकार को उन अत्यंत कठिन परिस्थितियों की जानकारी है, जिनके अंतर्गत हमारे बीच सशस्त्र सेनाएं हमारे देश की रक्षा करने के अपने कठोर दायित्वों को निभा रही हैं। हमारी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जबरन पड़ने पर अन्य मित्र देशों की सहायता करने के लिए आमंत्रित किए जाने पर हमारे देश का नाम ऊँचा करने के लिए पूरा देश उनके प्रति धन्यवाद का आभारी है। इसके साथ

हम सब इस बात को मानते हैं कि और रक्षा संबंधी श्रेष्ठ व्यवस्था में पहले से अधिक लागत संबंधी प्रभावोत्पादकता समावेश करने के लिए आवश्यक उपायों को कार्यान्वित करने की बराबर जरूरत है। रक्षा मंत्रालय में मेरे साथियों इस व्यवस्था की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने के लिए पहले बहुत से उपाय लागू किए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आगामी वर्ष में रक्षा के लिए 13,000 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है। मैं सदन को आश्वासन दूंगा कि अत्यंत उच्च-स्तरीय सुरक्षा संबंधी तैयारी की निश्चित व्यवस्था करने के मामले में सरकार कभी डील ही बरनेगी।

73. खाद्य पदार्थों, उर्वरकों और नियमित संवर्धन संबंधी आर्थिक सहायता देने के लिए अगले वर्ष के बजट में 7,472 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि चालू वर्ष के शोधित अनुमानों में 6,841 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। अनुमान है कि अगले वर्ष धान्य प्रभावों की राशि 17,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी जबकि चालू वर्ष में इन प्रभावों के रकम 14,150 करोड़ रुपए है। अनुमान है कि नवंबर आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्यों में चालू वर्ष में दिए गए अनुदानों के मुकाबले 612 करोड़ रुपए अधिक के अनुदान दिए जाएंगे। आम चुनावों के संबंध में किए जाने वाले व्ययों के लिए अगले वर्ष 152 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि डाक विभाग का घाटा चालू वर्ष के घाटे से 97 करोड़ रुपए घटा होगा।

74. आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि को रोकने के लिए प्रसन्न प्रयास किया गया है और बहुत ही जल्दी व्यवस्थाओं के लिए न्यूनतम मात्रा में अनुमति दी गई है। अनुमान है कि वर्ष 1989-90 में कुल आयोजना-भिन्न 54,347 करोड़ रुपए का होगा जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 48,877 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

75. जहाँ तक प्राप्तियों का संबंध है, अनुमान है कि कराधान की विद्यमान दरों पर सकल कर राजस्व के रूप में 49,588 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। राज्यों को करों के उनके हिस्से के रूप में 12,054 करोड़ रुपए और राजस्व के समन्वयन के रूप में मध्य राज्य क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को 50 करोड़ रुपए की अदायगी करने के पश्चात् केन्द्र को अनुमानित 37,484 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी, जबकि इसके मुकाबले चालू वर्ष में 32,652 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है। बाजार उधारों से 7,400 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है जबकि चालू वर्ष में 7,250 करोड़ रुपए की प्राप्ति आंकी गई थी। वापसी अदायगी की रकम घटाकर विदेशी सहायता से 3,722 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि चालू वर्ष में 3,216 करोड़ रुपए की प्राप्ति आंकी गई थी। अन्य प्राप्तियों और व्ययों की घटबढ़ को हिसाब में लेने के पश्चात् कराधान की मौजूदा दरों के अनुसार अगले वर्ष के बजट

में अनुमानित कुल बिनाकर 8240 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा।

भाग 'ख'

76. अब मैं वर्ष 1989-90 के लिए अपने कर प्रस्तावों की ओर आता हूँ।

77. अधिकांश लोगों के लिए कराधान कष्टप्रद है। मैं केवल यही कहूंगा कि हम एक व्यापक सामान्य प्रयोजन की प्राप्ति के लिए कराधान के जरिए संसाधन जुटाते हैं और यह प्रयत्न करते हैं कि लोगों को उस लागत से अधिक लाभ प्राप्त हो जो उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती है।

78. मेरे बजट प्रस्ताव उन्हीं उद्देश्यों और आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से मार्गदर्शित हैं जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है। विनिर्णय: मेरे प्रस्ताव निम्नलिखित उद्देश्यों के प्रति अभिमुख हैं:

—उत्पादक रोजगार का संवर्धन;

—गरीबों के खपत के स्तरों का संरक्षण;

—नीर अतिवार्य विनाशिता खपत को हतोत्साहित करना, विशेष रूप से यदि वस्तुओं का आयात किया जाता है,

—मध्यम आय वाले करदाताओं को कुछ राहत प्रदान करना;

—औद्योगिक आधुनिकीकरण और विकास की गति को बनाए रखना;

वर्ष 1989-90 के वजटीय घाटे को नियंत्रण में रखना।

79. अब मैं प्रत्यक्ष करों के संबंध में बजट प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा।

80. माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि सरकार उत्पादक रोजगार के सृजन को उच्च प्राथमिकता देती है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए रोजगार पैदा करने के वास्ते बहुत सी स्कीम पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं तथापि हमारा मन है कि अब समय आ गया है कि बेरोजगारी की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए उपाय किए जाएं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है, सरकार का प्रस्ताव अवाहलाल नेहरू रोजगार योजना नामक एक नये गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को शुरू करने का है। इन कार्यक्रम के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव उन आवासीय करदाताओं पर जिनकी वर्ष 1990-91 में कर निर्धारण वर्ष के लिए 50,000 रुपए से अधिक की आय हो, 8 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाने का है। मुझे विश्वास है कि अपने ऐसे समाज में जहाँ पर बहुत से लोग रोजगार से वंचित हैं, जिन लोगों का रोजगार का सीधे प्राप्ति है, वे अपने से कम भाग्यवान व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक यह स्वीकार करेंगे।

81. सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष करों की दरों में स्थिरता बनाए रखी है। तथापि प्रायः ऐसा कहा जाता रहा है कि प्रारंभ में 25 प्रतिशत कर के फलस्वरूप ऐसे बहुत से करदाताओं को हतोत्साहन मिलना है जो स्वेच्छा से कर देना चाहते हैं। तबनुसार 18,000—25000 रुपए के प्रारंभिक आय खंड वाले व्यक्तियों के लिए कर की दर को वर्तमान 25 प्रतिशत की दर से घटा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

82. सदन इस तथ्य से अवगत है कि वर्ष 1987 में पड़े सूखे और 1988 में उसके बाद के प्रभावों में संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से आय कर और धन कर पर अधिभार लगाया गया था। मैं वर्ष 1989-90 और वर्ष 1990-91 से क्रमशः धनकर और आयकर के अधिभार को जारी रखने का प्रस्ताव नहीं करना चाहता हूँ।

83. रोजगार अधिभार के संबंध में मैं जो प्रस्ताव कर रहा हूँ उनका तथा दर संरचना में परिवर्तनों का मिलाजुला प्रभाव यह होगा कि 56,000 रुपए से नीचे की कर योग्य आय वाले व्यक्ति को वर्तमान की तुलना से कम कर देना पड़ेगा। अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर का सम्पूर्ण बाझ उन व्यक्तियों पर पड़ेगा जिनको कर योग्य आय 56,000 रुपए से अधिक है। इन अधिभार से 500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदन सामाजिक प्रगति के इस उपाय का स्वागत करेगा।

84. अत्यधिक खपत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव व्यय कर अधिनियम, 1987 के अंतर्गत व्यय कर की दर को, जो कुछ होटलों पर लागू है, 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का है। इसके फलस्वरूप 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

85. अब मैं राहत प्रदान करने के लिए कुछ उपायों का जिक्र करूंगा :

86. नागरिकों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना सरकार का एक महत्वपूर्ण नीति-विषयक उद्देश्य रहा है। वर्ष 1987-88 के लिए अपने बजट भाषण में प्रधान मंत्री आवास क्षेत्र के लिए उच्च प्राथमिकता प्रदान करने की बात कही थी और एक राष्ट्रीय आवास बैंक स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की थी। इस संबंध में आवश्यक कानून पारित हो गया है और राष्ट्रीय आवास बैंक ने काम करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय आवास बैंक को उनकी प्रारंभिक अवस्था में संसाधन जुटाने में मदद देने के उद्देश्य से मेरा यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय आवास बैंक की "गृही ऋण खाता स्कीम" में जमा की जाने वाली राशि और साथ ही बैंक से लिए गए आवास ऋण की वापसी अवधि, आयकर अधिनियम की धारा 80 ग के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली कटौती के लिए पात्र होगी। 5 लाख रुपए की

अधिकतम सीमा तक के निवेश पर धन कर से भी छूट प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त करदाताओं को अब पूंजी लाभ पर धारा 54ए के अंतर्गत कर रियायत प्राप्त होगी यदि विक्रय से प्राप्त राशि का निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडों और ऋण को भुगतान कर दिया जाएगा।

87. मुर्गी पालन का व्यवसाय पोषण तत्व बढ़ाने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनता जा रहा है। इसलिए मेरा प्रस्ताव मुर्गीपालन व्यवसाय से होने वाली आय पर ऐसी आय के 33-1/3 प्रतिशत की दर से कर में छूट देने का है। इस उपाय से इस व्यवसाय में निवेश को प्रोत्साहित करने में बढ़ावा मिलेगा।

88. सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी प्रायः ऐसे निवेश अवसरों की तलाश में रहते हैं जहां से अच्छा उत्तर-कर प्रतिफल प्राप्त हो। इस उद्देश्य में जो ध्यान रखते हुए एक ऐसी जमा स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी अपने सेवा निवृत्ति लाभों को पूर्ण रूप में अथवा आंशिक रूप में तीन वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। इस निवेश पर प्राप्त होने वाला व्याज आय कर से मुक्त होगा। इसके अतिरिक्त यह निवेश धन कर से भी मुक्त होगा। कुछ विनिर्दिष्ट रूपों में धन के संबंध में 5 लाख रुपए तक की धन की छूट की वर्तमान सीमा भी ऐसी जमा राशि पर लागू नहीं होगी।

89. मृत कर्मचारियों की विधवाओं और उनके उत्तराधिकारियों को राहत प्रदान करने के एक उपाय के रूप में मेरा प्रस्ताव आय कर अधिनियम की व्यवस्थाओं को संशोधित करने का है ताकि परिवार पेंशन के प्राप्तकर्ताओं के लिए भी 12,000 रुपए की अधिकतम सीमा तक 33-1/3 प्रतिशत की दर से मानक कटौती का लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार, स्थायी रूप से शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले से उपलब्ध 15,000 रुपए की कटौती का लाभ मानसिक रूप से अवरूद्ध व्यक्तियों को भी प्रदान करने का प्रस्ताव है।

90. माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के अंतर्गत व्यवसायों पर कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है ताकि राज्य सरकारें अतिरिक्त संसाधन जुटाने में समर्थ हो सकें। मुझे उम्मीद है कि राज्य इसका पूरा लाभ उठाएंगे, मेरा प्रस्ताव है कि "वेतनों" के अंतर्गत आय का हिसाब लगाने में इस कर को एक कटौती के रूप में छूट दे दी जाए।

91. वर्ष 1988-89 के लिए बजट भाषण में की गई घोषणाओं के अनुसरण में सरकार ने एक्सचेंज जोखिम प्रशासन निधि स्थापित करने के संबंध में स्कीम तैयार की है और उच्च पूंजी कम्पनियों/निधियों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं ताकि नए उद्यमियों को सहायता प्रदान की जा सके।

इन निधियों के लिए राजकोषीय समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव उन्हें कतिपय कर रियायतें प्रदान करने का है।

92. प्रस्ताविन राहत उपायों के फलस्वरूप राजस्व हानि, यदि कोई हुई तो, बेहतर अनुपालन और बेहतर संग्रहण के जरिए पूरा हो जाने की उम्मीद है।

93. 7 नवम्बर 1988 को जारी की गई राष्ट्रपति की एक अधिसूचना द्वारा आयकर अधिनियम वर्ष 1989-90 के कर निर्धारण वर्ष से सिक्किम राज्य पर भी लागू हो जाना है। कुछ कार्यचालक संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अब मेरा प्रस्ताव आयकर अधिनियम 1961 को वर्ष 1990-91 के कर निर्धारण वर्ष से ही सिक्किम राज्य पर लागू करने का है। केन्द्रीय सरकार की एक अधिसूचना द्वारा धन कर अधिनियम और उपहार कर अधिनियम को वर्ष 1990-91 के कर निर्धारण वर्ष से पहले ही लागू किया जा चुका है।

94. अब मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्तावों की व्याख्या करूंगा।

95. इन प्रस्तावों को तैयार करने में मैंने अतिरिक्त साधन की अनिवार्यता से मार्गदर्शन प्राप्त किया। ऐसा करते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि जन-उपभोग की वस्तुओं पर अनुचित बोझ न पड़े और इन करों का भार मुख्यरूप से जनता के सापेक्षतया समृद्ध वर्गों पर ही पड़े।

96. जैसा कि सदन को ज्ञान है अवमूल्यंकन के जरिए उत्पादन शुल्क के अपवर्चन की समस्याओं और सम्बद्ध प्रशासनिक समस्याओं के कारण बहुत सी वस्तुओं पर मूल्यानुसार शुल्क लगाने की बजाय परिमाणानुसार शुल्क लगाना पड़ता है। वस्तुतः, कुल उत्पाद राजस्व का लगभग 70 प्रतिशत भाग परिमाणानुसार दरों पर शुल्कों वाली वस्तुओं से प्राप्त होता है। बहुत सी वस्तुओं के मामले में जिन पर परिमाणानुसार शुल्क की दरें लागू होती हैं, कर का भार उन पर मूल रूप से निर्धारित किए गए परिमाणानुसार शुल्कों की अपेक्षा काफी कम होना है। एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसके अनुसार सभी परिमाणानुसार दरों को मूल्य से वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बढ़ाया जा सके। मेरा प्रस्ताव इस संबंध में इसी बजट से शुरुआत करने का है और बहुत सों वस्तुओं पर वर्तमान दरों में पांच प्रतिशत की मामूली दर पर उपयुक्त रूप से पूर्णिक में बदल कर, विद्यमान परिमाणानुसार शुल्क दरों में वृद्धि करने का है। मैं यहां यह बता दूँ कि मैंने यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरती है कि आम खपत की वस्तुओं को इस समायोजन से अलग रखा जाए। जिन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा उनमें चीनी, चाय, काफी, मिट्टी के तेल, जीजन और मोटर स्प्रिट जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, बीड़ी, वनस्पति तेल, वनास्पति, सूती धागे और फेब्रिकस, जूट धागे और फेब्रिकस और विजली के बल्ब तथा फ्लोरोसेंट ट्यूबें

शामिल हैं। इसी प्रकार अखबारी कागज तथा पाठ्य पुस्तकों अथवा सामान्य हित की अन्य पुस्तकों के मुद्रण में उपयोग के लिए विशिष्ट कागज पर विद्यमान छूट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

97. आधा की जाती है कि परिमाणानुसार दरों में वृद्धि करने के फलस्वरूप 220 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पाद राजस्व प्राप्त होगा।

98. कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं जिन पर परिमाणानुसार दरों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और जिनके संबंध में सामान्य रूप से प्रस्तावित दर की अपेक्षा अधिक दर से समायोजन करने की आवश्यकता होगी। अब मैं इन वस्तुओं के संबंध में अपने प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा।

99. लोहे और इस्पात के मामले में पिछले एक दशक से अधिक समय से शुल्क की परिमाणानुसार दरों में कोई अधिक वृद्धि नहीं की गई है। राजस्व जुटाने के एक उपाय के रूप में मेरा प्रस्ताव इन मदों पर शुल्क की दरों में वृद्धि करने का है। पिघा आयरन पर शुल्क को 80 रुपए प्रति मी. टन से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति मी. टन करने का प्रस्ताव है। स्टेनलेस स्टील को छोड़ कर स्टील की अन्य मदों पर, जैसे कि लौह खण्ड बिलिट्स, सरियों, छड़ों पर, जिन पर इस समय 365 रुपए प्रति मी. टन का शुल्क लगता है, मेरा प्रस्ताव इस शुल्क को बढ़ा कर 500 रुपए प्रति मी. टन करने का है। शीटों, रिवटों आदि जैसे कतिपय तप्त वेल्लिन (हाईट रोल्ड) फ्लैट उत्पादों पर शुल्क को 500 रुपए से बढ़ा कर 700 रुपए प्रति मी. टन करने का प्रस्ताव है। शीटों और स्ट्रिप्स जैसे कतिपय शीत वेल्लिन (कोल्ड रोल्ड) फ्लैट उत्पादों के संबंध में शुल्क को 715 रुपए से बढ़ा कर 900 रुपए प्रति मी. टन करने का प्रस्ताव है।

100. डनार्ड और गवार्ड की वस्तुओं के मामले में कुछ कर निर्धारण संबंधी विवाद हैं क्योंकि शुल्क की दरें वर्गीकरण के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। इन्हें युक्तिसंगत बनाने के एक उपाय के रूप में और ऐसे विवादों की रोकथाम करने के लिये मेरा प्रस्ताव इस्पात गद्दी वस्तुओं पर 800 रु० प्रति मी० टन और इस्पात डली वस्तुओं पर 600 रु० प्रति मी० टन की एक समान दर में शुल्क लगाने का है।

101. स्टेनलेस स्टील के मामले में जिस पर शुल्क का बाझ अपेक्षाकृत कम है मेरा प्रस्ताव स्टील पिंडों, अर्द्धे निर्मित उत्पादों और तप्त वेल्लिन (हाईट रोल्ड) उत्पादों पर शुल्क की वर्तमान दरों को बढ़ाकर 100 रुपए प्रति मी० टन और कुछ शीत वेल्लिन (कोल्ड रोल्ड) उत्पादों पर 715 रु० प्रति मी० टन से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति मी० टन करने का है। स्टेनलेस स्टील डब्लो वस्तुओं और गद्दा वस्तुओं पर भी 1500 रुपये प्रति मी० टन का शुल्क लगेगा।

102. लौह तथा इस्पात की अन्य मदों पर भी ऐसे ही शुल्क संबंधी समायोजन करने का प्रस्ताव है। शुल्क योग्य तैयार शुद्ध उत्पादों के मामले में, लौह और स्टील मदों पर मोडवाट-क्रेडिट उपलब्ध होता रहेगा।

103. इन उपायों के फलस्वरूप अतिरिक्त उत्पाद राजस्व के रूप में 150 करोड़ रुपये तक की और सीमा शुल्क राजस्व के रूप में 18 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

104. कोई भी वित्त मंत्री इस प्रलोभन से अछूता नहीं रह सकता कि वह उत्पाद राजस्व में वृद्धि करने के लिये सिगरेट पीने वालों की आंखें देखे। मुझे यह स्वीकारना होगा कि मेरे अधिकांश पूर्ववर्तियों को तरह मैं भी इस प्रलोभन से नहीं बच सका हूँ। मेरे विचार में जो धूम्रपानकर्ता अपने स्वास्थ्य के संबंध में संविधिक चेतावनो पर ध्यान नहीं देते हैं उन्हें कम से कम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये अधिक अंशदान करना चाहिए। मेरा प्रस्ताव सिगरेटों पर शुल्क की दरों को पुनर्गठित करने का है। यद्यपि शुल्क दरों में यह वृद्धि सामान्य रूप से की जा रही है तथापि 70 मि.मी. से अधिक लम्बाई की फिल्टर सिगरेटों के मामले में यह वृद्धि ज्यादा होगी। 60 मि.मी. तक की लम्बी गैर-फिल्टर सिगरेटों पर 10 सिगरेट के प्रति पैकेट पर एक रुपये की दर से उत्पाद शुल्क लगेगा। इन उपायों से 101 करोड़ रुपये तक का उत्पाद राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

105. सिगरेटों पर शुल्क प्रणाली में संशोधन करने के बाद में पान मसाला उपयोग करने वालों को भी निराश नहीं करूंगा कि हमने उनका साथ छोड़ दिया है। मेरा प्रस्ताव तम्बाकू रहित पान बनाने पर कीमतों पर आधारित विद्यमान दो स्लेबों के लिये 10 रुपये और 20 रुपये के वर्तमान उत्पाद शुल्क को क्रमशः 20 रुपये और 40 रुपये प्रति कि.ग्रा. के हिसाब से दोगुना करने का है। इसके साथ ही मेरा प्रस्ताव तम्बाकू वाले पान मसाले पर उत्पादन शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का है। इन उपायों के फलस्वरूप आठ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

106. जैसा कि सदन को ज्ञान है, शराब बनाने के लिये शीरा (मालेस्स) एक प्रमुख कच्ची सामग्री है इसके अन्तर्गत उपयोग को ध्यान में रखते हुए मेरा मत है कि शीरे पर वर्तमान की तुलना में अधिक शुल्क लगाया जा सकता है। इसलिये मेरा प्रस्ताव शीरे पर उत्पाद शुल्क को 60 रुपये प्रति मी० टन से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति मी० टन करने का है। मेरा प्रस्ताव अल्कोहल का उपयोग रसायनों के विनिर्माण में किए जाने पर इस समय उपलब्ध मुद्रा को क्रेडिट में उपयुक्त वृद्धि करने का है। अनुमान है कि इन उपायों से 11 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त उत्पाद राजस्व प्राप्त होगा।

107. यात्रा कर के संबंध में मेरे कुछ एक प्रस्ताव हैं।

108. आजकल, निकटवर्ती देशों की यात्रा करने के लिये 50 रुपये प्रति टिकट की दर से और अन्य देशों की यात्रा

करने के संबंध में 100 रुपये प्रत्येक टिकट की दर से विदेश यात्रा कर लगाया जाता है। इन दरों में सन् 1979 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मेरा प्रस्ताव कर की उपरोक्त दरों को बढ़ाकर क्रमशः 150 रुपये और 300 रुपये करने का है।

109. जैसा कि सदन को जानकारी है, सरकार ने हमारे हवाई अड्डों को विकसित करने और वहाँ आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाएँ प्रदान करने पर काफी राशि का निवेश किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कुछ एक सुविधा सम्पन्न, व्यक्तियों को, जो देश के अन्दर हवाई यात्रा कर सकते हैं, राजस्व में वृद्धि करने के लिये कर के रूप में थोड़ी सी अतिरिक्त राशि अदा करने पर कोई आर्त नहीं होनी चाहिए। मेरा इरादा मूल किराए पर 10 प्रतिशत की दर से "अन्तर्-देशीय हवाई यात्रा कर" नामक एक नया कर लगाने का है। किन्तु मेरा प्रस्ताव विदेशी मुद्रा में हवाई किराया अदा करने वाले यात्रियों को इसके मुक्त रखने का है। कुछ पात्र विशेष श्रेणी के यात्रियों को भी इस प्रकार से कर से मुक्त रखने को व्यावस्था होगी।

110. यात्रा कर से संबंधित प्रस्तावों को लागू करने की तारीख बाद में अभिसूचित की जायेगी और इससे 85 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

111. विमानों में यात्रा करने वालों के बारे में कहने के बाद अब मैं उन लोगों के बारे में उल्लेख करूंगा, जो गाड़ी चलाते हैं, अर्थात् अब मैं आटोमोबाइल क्षेत्र के संबंध में अपने प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा।

112. जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञान है, इस समय 1000 सी.सी. से अधिक क्षमता वाले इंजन की ईंधन बचत वाली कारों के संबंध में 25 प्रतिशत और 1000 सी.सी. से अधिक क्षमता वाले इंजन की ऐसी कारों के संबंध में 30 प्रतिशत की रियायती दर से उत्पाद शुल्क लगता है जबकि अन्य कारों के संबंध में यह दर 35 प्रतिशत है। मेरा मत है कि ईंधन बचत वाली कारों ने अपना आधार प्राप्त कर लिया है और अब इन रियायती दरों को और आगे रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिये मेरा प्रस्ताव सभी मोटर कारों पर 35 प्रतिशत की एक समान दर से शुल्क लगाने का है। यह दर बैनों और जीपों पर भी लागू होगी। इस उपाय के फलस्वरूप 100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

113. आजकल 100 सी.सी. से अधिक क्षमता वाली दो-पहिया गाड़ियों पर 15 प्रतिशत की दर से और अन्यो पर 25 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगता है। मेरा प्रस्ताव दो-पहियों पर चार स्लैबों में उत्पादन शुल्क को पुनर्गठित करने का है। 50 सी.सी. तक के दो-पहियों पर शुल्क की दर 15 प्रतिशत के वर्तमान स्तर पर ही रहेगी। 50 और 100 सी.सी. के बीच दो-पहियों पर कर की 15 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। 100 और 150 सी.सी. के बीच दो-पहियों

पर 25 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क की दर से कोई परिवर्तन नहीं होगा। 150 से.मी. से ऊपर वाले दो-पहियों पर शुल्क की दर 30 प्रतिशत होगी। इस उपाय के फलस्वरूप लगभग 26 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

114. इनके घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रस्ताव इस क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क में कुछ रियायतें देने का है।

115. इसके बाद मेरा प्रस्ताव फ्यूल इंजेक्शन उपस्कर, जो आटोमोबाइल क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संघटक है के विनिर्माण के लिए आयातित मशीनरी पर 40 प्रतिशत का रियायती शुल्क भी निर्धारित करने का है। फ्यूल इंजेक्शन उपस्कर के विनिर्माण के लिए आयातित संघटकों पर भी यही दर लागू होगी। रियायती दर केवल उन्हीं यूनितों को उपलब्ध होगी जो एक अनुमोदित क्रमिक विनिर्माण के अन्तर्गत विनिर्माण करेंगे।

116. आटोमोटिव क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क में रियायत देने से राजस्व पर 19 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा।

117. अब मैं इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र के संबंध में उपायों के पैकेज का उल्लेख करूंगा। हमारी अर्थव्यवस्था में यह एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है और यह राजकोष में और अधिक अंशदान करने की स्थिति में है। इस क्षेत्र के संबंधित मेरे प्रस्ताव स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को और अधिक तेजी प्रदान करने के प्रति अभिमुख हैं।

118. सदन के सदस्यों को जानकारी है कि टेलीविजन से लोगों का काफी मनोरंजन होता है। यह अनुकूल ही होगा कि टेलीविजन का उपयोग करने वाले व्यक्ति, जो ऐसा मनोरंजन प्राप्त करते हैं, सरकार के संसाधनों में और इस प्रकार राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में और अधिक अंशदान करें।

119. इस समय 15 से.मी. से अधिक और 36 से.मी. तक के स्क्रीन वाले काले और सफेद टेलीविजन सेट उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त हैं। ऐसे सेटों पर छूट को जारी रखते हुए मेरा प्रस्ताव ऐसे सेटों की पिक्चर ट्यूब पर उत्पाद शुल्क को बढ़ा कर 200 रुपए प्रति ट्यूब करने का है। 36 से.मी. से अधिक स्क्रीन वाले काले और सफेद टेलीविजन सेट पर 300 रुपए प्रति सेट का उत्पाद शुल्क लगता है। मेरा प्रस्ताव इस दर को बढ़ा कर 500 रुपए प्रति सेट करने का है।

120. जहां तक रंगीन टेलीविजन सेटों का संबंध है इस समय 5,000 रुपए तक के निर्धारित मूल्य के प्रति सेट पर 1,500 रुपए और 5,000 रुपए से अधिक निर्धारित मूल्य के प्रति सेट पर 2,000 रुपए का शुल्क लगता है। इस शुल्क प्रणाली से मूल्यांकन संबंधी कुछ विवाद उत्पन्न

हुए हैं। बाजार में कुछ उंची कीमत वाले सेट भी आ चुके हैं, इसलिए रंगीन टेलीविजन सेटों पर शुल्क संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरा प्रस्ताव विना दूरस्थ नियंत्रण वाले प्रति सेट पर 2250 रुपए का, दूरस्थ नियंत्रण वाले प्रति सेट पर 2500 रुपए का और "पिकचर इन पिकचर" सुविधा वाले टेलीविजन के प्रति सेट पर 4000 का शुल्क निर्धारित करने का है।

121. मेरा प्रस्ताव रेडियो, टु-इन-वन, केमेट रिकार्डर और संगीत संबंधी प्रणालियों पर वर्तमान 15 प्रतिशत अथवा 20 प्रतिशत की दरों के मुकाबले 20 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने का है।

122. मेरा प्रस्ताव कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ा कर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का है। इसके साथ ही कम्प्यूटरों को लघु उद्योग के लिए छूट की सामान्य स्कीम से हटाया जा रहा है।

123. आजकल विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटकों के विनिर्माण के लिए आयातित विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री और हिस्से-पुर्जों पर क्रमशः 35 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क लगता है। शुल्क की इस रियायती दर को पहले से अधिक मदों के संबंध में लागू करने हुए मेरा प्रस्ताव इन दरों को बढ़ा कर क्रमशः 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत करने का है।

124. इलेक्ट्रॉनिक मदों से संबंधित इन प्रस्तावों से उत्पाद शुल्क में 158 करोड़ रुपए तक और सीमा शुल्क में 36.5 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

125. मैं इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क में कुछ रियायतों की भी घोषणा कर रहा हूं। पिछले वर्ष के बजट में, दूर संचार, उपग्रह, संचार, डाटा संचार, दूरदर्शन प्रसारण और स्टूडियो तथा ध्वनि प्रसारण के लिए बड़ी संख्या में उपस्करों के संबंध में 100 प्रतिशत के आयात शुल्क की एक समान दर निर्धारित की गई थी। मेरा प्रस्ताव इस रियायत को 35 और विनिर्दिष्ट उपस्करों तक बढ़ाने का है।

126. आण्टिकाल कम्प्यूटिकेशन केबल, दूर संचार के लिए आवश्यक है। देश में ऐसे केबलों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव उनके विनिर्माण के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क को 130 से लेकर 300 प्रतिशत तक की भिन्न-भिन्न वर्तमान दरों से घटा कर 80 प्रतिशत करने का है।

127. बृहद अमेरिकन मार्केट, माइक्रोप्रोसेसर तथा अन्य माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मद जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी मदों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मशीनरी की 22 मदों पर 15 प्रतिशत का रिधायती आयात शुल्क लिया जाता

है। मेरा प्रस्ताव इस रियायत को मशीनरी की पांच और मदों तक बढ़ाने का है।

128. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क में रियायतों में राजस्व पर 33 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा।

129. पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित सीमाशुल्क व्यवस्था के बारे में मेरे बहुत से उपाय हैं।

130. वर्ष 1987 का वजट प्रस्तुत करने समय माननीय प्रधान मंत्री ने पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग के महत्व पर जोर दिया था और कहा था कि हमारे समस्त प्रयास आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही केन्द्रित होने चाहिए। उस वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में उठाए गए। इन उपायों को लागू करने से जो सफलता हमें प्राप्त हुई है, उससे हमी रास्ते पर और आगे बढ़ते रहने का प्रोत्साहन हमें मिलता है। इसलिए मेरा पहला प्रस्ताव यह है कि प्रौद्योगिकी के स्तरवर्धन की योजना के अंतर्गत, पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माता उद्योगों के लिए किए जाने वाले मशीनरी के आयात पर जो शुल्क रियायत पहले दी गई है, उस रियायत को चार और क्षेत्रों में लागू कर दिया जाए। ये क्षेत्र कर्तक औजारों, वाणिज्यिक औजार कक्षाओं, वस्त्रोद्योग संबंधी मशीनरी और कागज तैयार करने की मशीनरी के हैं। इसके अलावा, जहाँ तक मशीनी औजारों के क्षेत्र का संबंध है, मैं ऐसी मशीनरी की मदों की सूची का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूँ जिन पर रियायती दर से शुल्क लिया जाता है।

131. मैं पूंजीगत वस्तुओं के आयात टेरिफ की व्यवस्था को भी युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। सामान्य परियोजनाओं और मशीनरी पर लगने वाले आयात-शुल्क की दर को इस समय प्रवर्तमान 90 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से कम करके 80 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। संघटकों पर शुल्क की दर जो मशीनरी पर लागू होने वाली दर से 15 प्रतिशत कम है, भी उतनी ही कम हो जाएगी।

132. इस दिशा में अगला कदम विनिर्दिष्ट मशीनरी पर लगने वाले रियायती आयात-शुल्क की दर को युक्तिसंगत बनाना है, जो कि इस समय 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच कमोवेश होनी रहती है। इस दर को इकट्ठा करके 40 प्रतिशत मूल्यानुसार के स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है किन्तु उर्वरकों से संबंधित परियोजनाओं के मामले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत परियोजनाओं के मामले में यह वृद्धि पांच प्रतिशत अंशों की रहेगी।

133. इन सब परिवर्तनों को लागू करने का औचित्य यह है कि जहाँ तक संभव हो सके टेरिफ की दरों में उपन्न होने वाले विक्षेप को कम किया जाए। इसलिए मैं 60 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से शुल्क के एक मध्यम

स्तर का निर्माण कर रहा हूँ। यह दर मशीनरी की उन कतिपय विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में लागू होगी, जिनका विनिर्माण अपने ही देश में होता है जिनमें आवद्ध विद्युत गयंत्र, कतिपय किस्मों के जेनरेटिंग सेट और जूट उद्योग में काम आने वाले वृत्तक लूम जैसी मद सम्मिलित हैं।

134. आधुनिक मशीनरी का आयात करके अपनी प्रौद्योगिकी का स्तरवर्धन करने के लिए निर्यात-प्रधान क्षेत्रों को पर्याप्त सुविधा देने के उद्देश्य से, विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम आने वाली मशीनरी के संबंध में समय-समय पर शुल्कों की रियायती दरें निर्धारित की जाती रही हैं। मैं यह रियायत रबड़ और केनवास फुटवीयर क्षेत्र को भी देना चाहता हूँ और इसी प्रयोजना के लिए वस्त्रोद्योग तथा रेशमकीट-पालन उद्योग क्षेत्रों की मशीनरी की विद्यमान सूची का भी विस्तार करना चाहता हूँ।

135. अनुमान है कि पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में इन उपायों को लागू करने से लगभग 117 करोड़ रुपए के सीमा-शुल्क राजस्व की हानि होगी।

136. जैसा कि मैंने अपने भाषण में पहले कहा है, एल्युमिनियम के मूल्यनिर्धारण और संवितरण पर से नियंत्रण तत्काल समाप्त किया जा रहा है। किन्तु इस सन्दर्भ में मैं एल्युमिनियम के डलों और तंतु छड़ों (वायर रॉड) के उत्पाद-शुल्क को 18 प्रतिशत मूल्यानुसार के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसमें प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से 2500 रुपए और जोड़ दिए जाएंगे। शुक्ति प्रारंभिक एल्युमिनियम के संबंध में मोडवाट क्रेडिट कारखानों में तैयार हुए शुल्क-निर्धारण योग्य उत्पादों के संबंध में उपलब्ध होगा, इसलिए मैं ऐसे अधिकतर उत्पादों के शुल्क में दस प्रतिशत अंश की वृद्धि करना चाहता हूँ। एल्युमिनियम की छड़ों पर लगने वाले बुनियादी और सहायक सीमा-शुल्कों से भी छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। एल्युमिनियम की छीजन (स्क्रैप) पर लगने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। इन उपायों से कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपए के निवल राजस्व की प्राप्ति होगी।

137. कतिपय वस्तुएं ऐसी भी हैं, जिन पर इस समय कम दर से सीमा-शुल्क लगाया जाता है और इसलिए इन वस्तुओं के शुल्क पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं लकड़ी के गूदे, रही कागज, कम राख वाले कोयले, कच्चे पेट्रोलियम, कोक और कतिपय रसायनों के आयात-शुल्क की मौजूदा दरों में पांच प्रतिशत अंश की वृद्धि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह प्रस्ताव भी रखता हूँ कि बेन्जीन के बुनियादी सीमा-शुल्क की वर्तमान शून्य दर को बढ़ाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। इन प्रस्तावों से 39 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी।

138. मैं काचित अख्तवारी कागज (स्लेज्ड न्यूजप्रिंट) के वृन्धायती सीमा-शुल्क को 550 रुपए प्रति मीट्रिक टन की मौजूदा दर से बढ़ाकर 30 प्रतिशत मूल्यानुसार करना चाहता हूँ। इससे लगभग 12 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व का लाभ होगा।

139. इस समय, घड़ियों और उनके संघटकों पर 2 प्रतिशत मूल्यानुसार की कम दर के हिसाब से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। यह दर घड़ियों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निर्धारित की गई थी। यह उपाय सफल रहा। मेरा विचार है कि अब वह समय आ गया है जब घड़ी विनिर्माता उद्योग अपेक्षमता ऊँचे उत्पाद-शुल्क के भार को सहन कर सकता है। मैं शुल्क दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप 5 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी।

140. अब मैं कृषि पर आधारित और तत्संबद्ध अन्य उद्योगों के बारे में प्रतिपादित अपने प्रस्तावों का भी उल्लेख करूँगा।

141. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है खाद्य संसाधन और पैकेज बंधन उद्योग की वृद्धि कृषि-उत्पादों के मूल्य में और अधिक संबंधन करने और किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए अनिवार्य है। पिछले वर्ष खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए शीतागारों की स्थापना करने में प्रयुक्त होने वाले घटकों और सहायक पुर्जों के उत्पाद-शुल्क को बजट-प्रस्तावों के माध्यम से 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया था। अब मैं 15 प्रतिशत की इस रियायती दर को प्रशीतक एन्हांस और मशीनरी के हिस्सों तथा कम्प्रेसरों पर भी लागू करना चाहता हूँ, जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों और डेरी उत्पादों के परिवहन के लिए बनाई जाने वाली प्रशीतित गाड़ियों में किया जाता है।

142. इस समय खाद्य संसाधन और पैकेजबंधन मशीनरी की 31 विनिर्दिष्ट मर्दों पर 35 प्रतिशत की रियायती दर से आयात-शुल्क लगाया जाता है। मैं शुल्क की इस रियायती दर को मशीनरी की कुछ और विनिर्दिष्ट मर्दों, अर्थात् परिवहन प्रशीतन एककों और अंडा संसाधन मशीनरी के संबंध में भी लागू करना चाहता हूँ। जैसा कि पहले कहा गया है, शुल्क की इस रियायती दर को अब 40 प्रतिशत के स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है।

143. मैं मखनिया दूध के पाउडर और मधुनित्र दूध पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क की दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। इसके साथ-साथ मखनिया दूध के पाउडर के एक किनोग्राम के डिब्बे पर दी गई उत्पाद-शुल्क की छूट को भी वापस लिया जा रहा है। कतिपय अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पाद-शुल्क की दर को भी, जैसे मछली, मांस में बने डिब्बाबंद टेपिओका

तथा सागो, पदार्थों के शुल्क की दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है। भुजिया और चबैना जैसे नमकीन खाद्यपदार्थों और इडली सम्मिश्र (मिक्स) तथा बड़ा सम्मिश्र जैसे तुरंत पकाए जा सकने वाले विनिर्दिष्ट सम्मिश्रों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी जा रही है।

144. समुद्री खाद्य पदार्थ क्षेत्र के लिए उपयोगी मशीनरी की कतिपय विनिर्दिष्ट मर्दों के लिए 61 प्रतिशत की रियायती आयात-शुल्क की दर निर्धारित है। मैं इस दर को और कम करके 40 प्रतिशत करने और रियायत प्राप्त वाली मर्दों की सूची को उसमें मत्स्य ग्रहण संबंध मशीनरी की तीन और मर्द जोड़कर पहले से ज्यादा विस्तृत बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं मछली पकड़ने के जाल तैयार करने के काम आने वाली मशीनरी के आयात-शुल्क को 90 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

145. सितंबर, 1988 में घोषित बीज विकास संबंधी नई नीति में विहित प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव का संबंध बीज उत्पादन और संसाधन तथा कोटि नियंत्रण के काम आने वाली ऐसी मशीनों और ऐसे उपकरणों के आयात-शुल्क में कमी करने से है, जिनके लिए प्रयोगिकी का स्तरवर्धन आवश्यक है। मैं ऐसी मशीनरी और ऐसे उपकरणों की 12 विनिर्दिष्ट मर्दों पर 40 प्रतिशत की रियायती दर से आयात-शुल्क लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

146. मुर्गीपालन के लिए आवश्यक मुर्गी दान की गुणावस्था में सुधार करने के उद्देश्य में मैं दा विनिर्दिष्ट एमिनो एसिडों के आयात-शुल्क को 147.25 प्रतिशत को वर्तमान स्तर से घटाकर 70 प्रतिशत के स्तर पर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

147. जूट उद्योग को राहत देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसी पंजीबद्ध हथकरघा सहकारी समितियों अथवा संगठनों को सप्लाई किए गए जूट के धान पर उत्पाद-शुल्क से छूट दे दी जाए, जिनको सरकार ने स्थापित या अनुमोदित किया हो। यह छूट जूट के धूलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फेब्रिक से भिन्न फेब्रिकों के विनिर्माण के लिए हथकरघों के विकास के प्रयोजन की सिद्धि के लिए उपलब्ध की जाएगी। मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और बोर्डों के द्वारा स्थापित किए गए एककों के संबंध में भी इस छूट को दिए जाने का प्रस्ताव करता हूँ।

148. वजन के अनुसार कम से कम 75 प्रतिशत बर्गीय कागज और गत्ते पर उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट मिली हुई है। कागज के विनिर्माण के लिए गैर-परंपरागत कच्चे माल के उपयोग को और बढ़ावा देने के प्रयोजन से और वनजान कच्ची सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करने की प्रवृत्ति को काम करने के लिए मैं उत्पाद-शुल्क की इस रियायत को कागज और गत्ते की उन किस्मों पर भी लागू करना चाहता हूँ,

जिनके निर्माण में कच्ची जूट अथवा मेस्ता से बना कम से कम 75 प्रतिशत गुदा इस्तेमाल में लाया जाता है। प्राथमिक रूप से यह उपाय जूट उद्योग के लिए सहायक सिद्ध होगा।

149. किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत दिलवाने में सहायता करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बालचीनी के बुनियादी सीमा-शुल्क की दर को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ाकर 90 प्रतिशत मूलानुसार कर दिया जाए, जिसमें प्रति किलोग्राम के हिसाब से 20 रुपए और जोड़ दिए जाएं और लौंग के बुनियादी सीमा-शुल्क की दर को 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ाकर 95 रुपया प्रति किलोग्राम कर दिया जाए।

150. खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के उत्पादों के बिक्री को भारी बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं ऐसे उत्पादों के संबंध में जिनपर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और बोर्डों का ब्रांड नाम अंकित हो, छोटे पैमाने के उत्पादन से संबंधित रियायत को विशेष रूप से जारी रखे जाने का प्रस्ताव करता हूँ। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा अथवा उसकी सहायता से बेचे जाने वाले ग्रामीण उद्योगों में बने उत्पादों के संबंध में इस समय जो रियायत उपलब्ध है वही रियायत फर्नीचर और चीनी मिट्टी के उत्पादों के संबंध में भी दी जा रही है।

151. कृषि पर आधारित और तत्संबद्ध उद्योगों से संबंध रखने वाले इन उपायों के परिणामस्वरूप 5 करोड़ रुपए के सीमा-शुल्क राजस्व और 8 करोड़ रुपए के उत्पाद-शुल्क राजस्व की हानि होने का अनुमान है।

152. दियामलाई उद्योग के उत्पाद-शुल्कों के ढांचे पर पुनर्विचार करने के पश्चात् मैं महसूस करता हूँ कि इस उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में निर्धारित शुल्क दरों में संशोधन करने की आवश्यकता है। इस समय इस उद्योग के यंत्रचालित, अर्धयंत्रचालित, यंत्र व्यवस्था विहीन और कुटीर स्तर के क्षेत्रों पर क्रमशः 5.85 रुपए, 4.15 रुपए, 3.50 रुपए और 1.60 रुपए प्रति गुर्स बक्सों के हिसाब से उत्पाद-शुल्क लगाया जाता है। मैं उपर्युक्त दरों को कम करते क्रमशः 4.50 रुपए, 3.00 रुपए, 2.50 रुपए और 1.10 रुपए प्रति गुर्स करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके साथ ही मैं पोटाशियम क्लोरेट के उत्पाद-शुल्क को भी, जो कि दियामलाईयों के विनिर्माण के काम में आने वाली अनिवार्य कच्ची सामग्री है, 15 प्रतिशत मूलानुसार से बढ़ाकर जो कि स्थूलतया 2 रुपया प्रति किलोग्राम के बराबर बैठता है, 5 रुपया प्रति किलोग्राम करना चाहता हूँ। शुल्क दरों को पहली जून, 1989 से प्रति 100 बक्सों के हिसाब से मीट्रिक पद्धति अनुसार तथा परिमाणानुसार रूपांतरित कर दिया जाएगा। इन प्रस्तावों के कारण 11 करोड़ रुपए के उत्पाद-शुल्क राजस्व की हानि होगी।

153. सूखे के कारण कपास की कमी हो जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष बजट प्रस्तावों के माध्यम

से सूत के साथ सम्मिश्रण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बिस्काय स्टेपल फाइबर के संबंध में 5.22 रुपया प्रति किलोग्राम के रियायती शुल्क की दर निर्धारित की गई थी। किन्तु इस वर्ष कपास की उपलब्धता में वृद्धि हो जाने के कारण इस रियायत को और आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस रियायती दर को वापस लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ और बिस्काय स्टेपल फाइबर के संबंध में 8.35 रुपए प्रति किलोग्राम की एक अमान दर के हिसाब से शुल्क आरोपित करना चाहता हूँ। इस उपाय से 14 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी।

154. मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और राज्यों के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के द्वारा आयात की जाने वाली कच्ची ऊन पर शुल्क को पूरी छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

155. कच्चे रेशम की सीमा-शुल्क दर को 75 प्रतिशत मूलानुसार से घटाकर 50 प्रतिशत मूलानुसार किया जा रहा है।

156. रंजक पदार्थ (डाइस्टक) वस्त्र संसाधन की प्रक्रिया में कम आने वाले महत्वपूर्ण साधक पदार्थ है। इन पर इस समय 35 प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क लगाता है। मैं संश्लिष्ट आर्गेनिक रंजक पदार्थों के उत्पाद-शुल्क की दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत का देने का प्रस्ताव रखता हूँ। इस प्रस्ताव के कारण, जिससे वस्त्रोद्योग से संबद्ध उद्योग धंधों को लाभ पहुंचेगा, 19 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

157. 60 रुपए प्रति वर्गमीटर तक के मूल्य के संश्लिष्ट शोशी कम्बलों के संबंध में उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट दी जा रही है।

158. मैं विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधों और औषधिक मध्यवर्ती पदार्थों के सीमा-शुल्क में कतिपय रियायतें देने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करता हूँ। इस क्षेत्र में दी जाने वाली रियायतों के परिणामस्वरूप लगभग 7 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

159. उर्वरकर शफ्ट वाले भट्टों का उपयोग करने वाले सीमेंट के एककों को रखने देने के प्रयोजन से मैं ऐसे एककों के द्वारा विनिर्माण सीमेंट पर लगे वाले उत्पाद-शुल्क की सामान्य प्रभावी दर में 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से कमी करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इस प्रस्ताव से 10 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

160. ऊर्जा के संरक्षण के उद्देश्य से मैं उच्च दाय युक्त मोडियम वॉलर लैम्पों के उत्पाद-शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी के साथ-साथ मैं ऐसे लैम्पों के विनिर्माण में काम आने वाली चार विनिर्दिष्ट निविष्टियों पर भी 50 प्रतिशत की रियायती

दर से आयात-शुल्क तगाए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ। इन रियायतों के परिणामस्वरूप उत्पाद-शुल्क राजस्व में 2.5 करोड़ रुपए और सीमा-शुल्क राजस्व में 5 करोड़ रुपए की हानि होगी।

161. बहुत से अर्थविद्वान प्राप्त हुए हैं कि बीडियो के माध्यम से की जाने वाली दस्तुता के कारण फिल्म उद्योग पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए मैं वृत्त चित्रों के उत्पाद-शुल्क की दरों की पुनर्व्यवस्था करना चाहता हूँ। संशोधित प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक वृत्त चित्र के पहले 30 प्रिंटों पर उत्पाद-शुल्क की पूरी छूट प्राप्त होगी, जबकि इस समय ऐसी छूट पहले 12 प्रिंटों के संबंध में उपलब्ध है। बाद के प्रिंटों पर लगने वाले शुल्क की दरों को भी कम किया जा रहा है।

162 शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्य में जुटे हुए कुछ संगठन ऐसे व्यक्तियों को रोजगार सृष्टि करने के लिए विनिर्माण का कारोबार भी करते हैं। इस समय ऐसे संगठनों को उत्पाद-शुल्क की उतनी ही छूट प्राप्त करने का हक है जितनी छूट छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में विनिर्मित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में उपलब्ध है। मैं इन संगठनों के द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुओं को पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

163 रसायन उद्योगों और पर्यावरणिक नियंत्रण से संबंधित क्रियाकलापों में सुरक्षा की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मैं 25 विनिर्दिष्ट उपस्करों अर्थात् खनरत्नाक रासायनिक पदार्थों अथवा गैसों और विशेष दाहक संरचनाओं आदि जैसे उपस्करों पर 40 प्रतिशत की रियायती दर से आयात-शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

164. पैराक्सिलीन एक ऐसी महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है, जिसका उपयोग डी.एम.टी. और पी.टी.ए. के विनिर्माण में किया जाता है और इन उत्तरोक्त पदार्थों का उपयोग आगे चलकर पॉलिएस्टर उद्योग द्वारा किया जाता है। पैराक्सिलीन के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के क्षेत्र में प्रवर्तमान हाल ही की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए मैं पैराक्सिलीन के आयात-शुल्क की दर को 120 प्रतिशत से घटाकर 90 प्रतिशत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

165. सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों के क्षेत्र में व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने और शुल्कों के अपव्ययन की रोकथाम करने के लिए भी कुछ एक उपाय किए जा रहे हैं।

166 इस समय पेट्रो-रासायनिक कारखानों की कतिपय रियायतें प्राप्त करने का हक है, जिनमें नेफ्था के संबंध में उत्पाद-शुल्क संबंधी वह रियायत भी शामिल है जो उपर्युक्त कारखानों को उस समय प्राप्त होती है जबकि उनको शोधन-शालाओं के रूप में घोषित कर दिया जाता है। इस वर्तमान योजना पर फिर से विचार किया गया है और मैं इन

रियायतों को, कारखानों की शोधनशाला घोषित करने की शर्त से जोड़े बिना कुछ परिवर्तनों के साथ बराबर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ-साथ मैं कच्चे नेफ्था के शुल्क की रियायती दर को 30 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 60 रुपया प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करता हूँ। कतिपय कारखानों को शोधनशालाओं के रूप में घोषित किए जाने के लिए जारी किए गए आदेशों को रद्द किया जा रहा है।

167. छोटे एककों को 30 लाख रुपए मूल्य के उत्पादन तक उत्पाद-शुल्क से तब छूट दी जाती है जब वे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ के एक से अधिक शीषों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का विनिर्माण करते हों। मैं इस योजना को पुनः व्यवस्थित करने का प्रस्ताव रखता हूँ, जिससे कि 30 लाख रुपए के मूल्य के उत्पादन पर उसी दशा में छूट दी जा सके, जबकि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ के एक से अधिक अध्याय के अन्तर्गत सम्मिलित वस्तुओं का विनिर्माण उनमें किया जाता हो।

168. जिन उपायों की घोषणा की गई है, उनके राजस्व-विषयक प्रभाव का ब्यापक वित्त विधेयक के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

169. सहायक सीमाशुल्कों और विशेष उत्पाद शुल्कों को मौजूदा दरों पर लागू रखने की व्यवस्था वित्त-विधेयक में की जा रही है।

170. उपर्युक्त प्रस्तावों के अलावा मैंने उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क टेरिफ में परिवर्तन करने के आशय से वित्त विधेयक में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। ये संशोधन मात्र सक्षमता प्रदान करते वाले उपबंध हैं और राजस्व उपार्जन की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ एक मौजूदा अधिसूचनाओं में भी संशोधन करने के प्रस्ताव किए जा रहे हैं। इस सदन का मूल्यवान समय बचाने के लिए मैं उन सब प्रस्तावों को दोहराना नहीं चाहता।

171. कुल मिलाकर संक्षेप में सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों की व्यवस्था में प्रस्तावित इन परिवर्तनों के परिणाम-स्वरूप उत्पाद-शुल्कों से 863.20 करोड़ रुपए और सीमा-शुल्कों से 117.06 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। जिन रियायतों और राहतों की घोषणा की गई है उनके अनुसार सीमा-शुल्कों के क्षेत्र में कुल मिलाकर 237.12 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों के क्षेत्र में 71.02 करोड़ रुपए की रियायतें और राहते दी जा रही हैं। इस प्रकार उत्पाद-शुल्कों से 792.18 करोड़ रुपए के निवल अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। सीमा-शुल्कों के संबंध में 120.06 करोड़ रुपए के राजस्व की निवल हानि होगी। इसके अतिरिक्त विदेश यात्रा कर में

किए जाने वाले परिवर्तनों और अंतर्देशीय यात्रा कर को आरोपित करने से 85 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। अतएव, अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाले 757.12 करोड़ रुपए के कुल निवल अतिरिक्त राजस्व में केन्द्र के हिस्से में 373.13 करोड़ रुपए और राज्यों के हिस्से में 383.99 करोड़ रुपए की राशि आएगी।

172. औषधीय और प्रसाधन निर्मित (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद 268 के अन्तर्गत अधिनियमित एक ऐसा कानून है जिसके उपबंधों के अनुसरण में शुल्क तो मंघीय सरकार के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, किन्तु उनका संग्रह और वित्तियोग राज्यों के द्वारा किया जाता है। मद्यसार (अल्कोहल), मादक द्रव्य तथा मादक औषधों से युक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर लगने वाले शुल्कों की दरों में वर्ष 1982 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं कि इन दरों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और इनमें उपर्युक्त मंशोधन भी किए जाने चाहिए। यद्यपि मैं शुल्कों की मूल्यानुसार दरों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता तथापि मैं शुल्क की परिमाणानुसार दरों में मौजूदा दरों के लगभग 50 प्रतिशत के बराबर की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। अनुसूची में किए गए परिवर्तनों का विवरण वित्त विधेयक के व्याख्यात्मक भाषण में प्रस्तुत किया गया है।

173. प्रवर्तमान सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों के परिवर्तनों को पहली मार्च 1989 से प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियों को उचित समय पर समा-पटल पर रख दिया जाएगा।

174. प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में जिन परिवर्तनों का प्रस्ताव मैंने किया है, उनके आधार पर केन्द्र को 903 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है। इनको हिसाब में लेने के पश्चात् अनुमान है कि अगले वर्ष के अंत तक 7,337 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा।

175. महोदय, जो प्रस्ताव अभी मैंने प्रस्तुत किए हैं, वे समग्र रूप में सामाजिक न्याय की स्थापना करने के हमारे सतत अन्वेषण के उद्देश्य की पूर्ति की ओर अग्रसर होने वाले मार्ग में गुणात्मक आधार पर एक नए चरण के परिचायक हैं। यह नया रोजगार कार्यक्रम, जो कुछ समय पश्चात् दूर-दूर तक फैल जाएगा, जनता का अपना कार्यसाधक गन्त है, जिसका प्रयोग निर्धनता के बन्धनों से मुक्त समाज का अंग बनाने के लिए जनता स्वयं कर रही है। ये बजट प्रस्ताव आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सरकार के दृढ़ संकल्प के भी परिचायक हैं। हम निर्यात संबंधित, भारतीय उद्योगों के आधुनिकीकरण और कुशल आयात-प्रतिस्थापन की नीतियों को जोरदार ढंग से कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इन वित्तीय नीति संबंधी परिमितियों के अंतर्गत रहते हुए आयात के परिमाण को उचित स्तरों तक सीमित रखने

के लिए समस्त प्रयास किए जाएंगे। विकास के मार्ग की ये यात्रा बड़ी कठिन और लम्बी है। इसके लिए बलिदान देना पड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है कि भावी विकास और समृद्धि के लिए ऐसा बलिदान कौन करेगा। प्रस्तुत बजट-प्रस्तावों में इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट और निश्चित रूप से दे दिया गया है। सपेक्षिक रूप से समृद्ध लोगों को ही अधिक भाग सहन करना होगा ताकि समाज के कमजोर वर्गों के लोग समृद्धि के मधुर फल को प्राप्त करने के हिस्सेदार बन सकें।

186. मैं इस बजट को स्वीकृति के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

के.बी.आर. नायर, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

BUDGET DIVISION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1989

M/Finance (DEA) U.O. No. 15(95)-B(D)/88.—The following is published for general information of the Public:—

Budget 1989-90

Speech of

Shri S. B. Chavan

Minister of Finance

28th February, 1989

PART A

Sir,

I rise to present the Budget for the year 1989-90. The Budget is an instrument for achieving the basic objectives of planned development which, broadly, are growth, modernisation, self-reliance and social justice. In each of these areas, we have made substantial progress. There are clear signs of an acceleration in the growth rate of our economy during the eighties. The pace of modernisation, particularly in industry and infrastructure has increased greatly because of the policies pursued by us for the past few years. The movement towards self-reliance has been maintained by the sustained growth in exports. And most important of all, our commitment to the goals of social justice has been demonstrated in the major initiatives that we have taken in anti-poverty and employment programmes and in the fulfilment of essential needs. These long-term objectives provide the framework within which the Budget for 1989-90 has been formulated.

2. The Annual Budget has to pursue these long-term objectives within the context of the short-term economic situation. The Economic Survey for the year 1988-89, which was laid on the Table of the House a few days ago, deals with the economic situation in some detail. I will only highlight a few key points.

3. The performance of the Indian economy in the past few years has shown unmistakable features of strength. The first is the resilience of the economy when confronted with the severe disruption caused by drought and floods. Last year, my predecessor, when presenting the Budget, had referred to this and indicated that the gross domestic product would grow perhaps by 1 to 2 per cent. I am happy to

inform the House that the latest estimates of economic performance in the drought year or 1987-88 indicate that, despite the drought, GDP grew by 3.6 per cent. This commendable performance in a year of drought has been followed by vigorous growth in the current year and we expect the GDP to grow by 9 per cent or more in real terms. Both the rate of growth of GDP in the drought year and the pace of recovery in the post-drought year, are significantly higher than those in earlier periods of drought. I may add that the average growth rate of GDP in the first four years of the Plan will exceed the Plan target of 5 per cent.

4. The performance in the agricultural sector in these past two years gives grounds for hope. Last year, despite the severe drought and floods, foodgrains production was 138 million tonnes, only marginally lower than in the previous year, showing that our policies to contain the impact of the drought were successful. This year, foodgrains production is expected to exceed the target of 166 million tonnes. Oilseeds, cotton and sugar production are expected to reach record levels. The sector continues to demonstrate a high potential for growth.

5. The growth in output in a period of stress, the careful management of the food economy by the Government, and the special measures taken to boost agricultural production and provide relief to those affected by drought have ensured that inflation, as measured by the Wholesale Price Index, was limited to 10.6 per cent in 1987-88. The rate of inflation in the current year has been under 5 per cent up to the end of January, 1989. Government is concerned about the pressure on prices, but it is a matter of some satisfaction that this pressure has been generally lower than in previous droughts. Government remains fully vigilant on this crucial front and are determined to ensure effective containment of inflation.

6. The second encouraging feature of economic performance in recent years, is the sustained growth of industrial sector and improved performance in the field of infrastructure. For 4 years in succession, manufacturing output has grown by over 8 per cent per year which is a clear vindication of the industrial policy of the Government. There is a spirit of optimism in industry which is reflected in the generally good corporate performance and buoyant conditions in the capital market. Electricity generation has increased steadily and the plant load factor of thermal plants has gone up from 50.1 per cent in 1984-85 to 56.5 per cent in 1987-88. Targets for capacity creation in the power sector set for the Seventh Plan are expected to be achieved. In the Railways the quantity of freight carried has increased in the first three years of the Seventh Plan by an amount as large as the total increase over the previous 10 years. More important, there has been a steady improvement in productivity over these years. A particularly welcome feature is the improvement in the performance of the basic materials industries. In the first nine months of this year, production of saleable steel by the integrated steel plants rose by 10.1 per cent, of cement by 12 per cent, nitrogenous fertilisers by 26.2 per cent and phosphatic fertilisers by 64.5 per cent when compared with the corresponding period last year.

7. The performance of Central Public Sector Enterprises has shown improvement. In the first six months of this year the provisional results of 179 operating enterprises show that their net profit rose to Rs. 694.19 crores from Rs. 59.79 crores in the corresponding period of 1987-88.

8. We are committed to a policy of supporting the growth of our public sector. However, we recognise that some changes are required to ensure a higher level of performance, particularly with regard to resource generation. With a view to granting greater autonomy to public sector enterprises consistent with their accountability, the Government has been signing Memoranda of Understanding with some of the Public Sector Undertakings. The MOU indicates the responsibilities of the enterprise in fulfilling certain physical, financial and social objectives including resource generation, and of the Government, in turn, for supporting the enterprise in fulfilling various objectives and targets set for the enterprise. Eleven

Public Sector Undertakings signed MOUs with the Government for the year 1988-89. Seven more Public Sector Undertakings will sign MOUs for the year 1989-90. The Government has constituted a High Level Committee under the Chairmanship of Cabinet Secretary to evaluate the performance of MOU signing companies and their administrative Ministries in fulfilling their obligations under the MOU.

9. I have referred to the resilience of the economy and the improved growth performance in industry and infrastructure because these are the strengths that will allow us to pursue even more vigorously our basic objectives of raising the living standards of the poor and strengthening the economic independence of our country. But I would be failing in my duty if I do not also draw the attention of the House to certain problem areas.

10. One area that needs more attention is the stimulation of savings and the containment of the budget deficit. We have always prided ourselves on being a nation with a high savings rate, and our culture has always emphasised the virtues of simple living and frugality. Budgetary policy must reinforce these virtues of thrift both through positive incentives to stimulate savings and through measures to restrain luxury consumption. I will indicate later in the speech the specific measures that we propose to take towards this end.

11. Equally important, and in some sense more significant, is the prudent management of public expenditure. Sometimes, it is assumed that Government expenditure, as commonly understood, is all on the wages and salaries of Government servants and on goods and services purchased by the Government Departments to fulfil their functions. This is far from being the case. In actual fact, the direct consumption expenditure of the Central Government on defence and Government Administration is less than one quarter of the total expenditure. A little under one tenth of the Budget is for the direct capital expenditure of the Central Government. As much as two-thirds of the Budget expenditure really take the form of financial transfers to other spending entities by way of interest, subsidies, grants, loans, etc. In fact, a significant part of what is shown as expenditure in the Budget is only the financial intermediation of funds shown as a capital receipt on the one side and as expenditure in the form of loans or equity investment on the other.

12. I am drawing attention to the structure of the expenditure side of the Central Budget in order to emphasise that the exercise of due prudence is not merely a matter of economy instructions regarding staff or travel or purchases. That is certainly important. But it is as important, in fact even more important, to consider other items of expenditure like subsidies, grants and loans, many of which are embedded in specific schemes and programmes. We must ask ourselves whether we are getting value for money from these subsidies, schemes and programmes. In many cases the desired result could be achieved at lesser cost by better targeting consolidation of multiple programmes, greater decentralisation linked to mobilisation of local resources. We will ensure that such an evaluation forms the basis for the schemes/programmes that will form part of the Eighth Plan.

13. The balance of payments is another area of concern. A certain amount of pressure on external payments is unavoidable in a situation where we have urgent needs for investment and modernisation which inevitably require expansion of imports. It is for this reason that Government have attached high priority to expanding exports to pay for the imports the economy needs. Our policies in this regard have been successful and in the past two years our exports have increased quite rapidly over 25 per cent in 1987-88 and 24 to 25 per cent in the first nine months of the current financial year. But at the same time, the import bill has also increased sharply, especially so in the first half of this year. This surge in the import bill is partly due to the foodgrains and edible oil imports necessitated by last year's drought and partly to the sharp increase in the international prices of metals, chemicals and edible oils. Apart from this, our debt repayment liabilities were relatively high. The limited availability of concessional finance has compelled us to increase the share of commercial borrowings, but we have tried to keep these within limits that are manageable. We do not envisage any difficulty in servicing our external debt.

14. The Indian economy has a great deal of underlying strength. The sustained growth of industrial sector and the investments made in modernisation and upgradation will show results in terms of higher exports. This in fact is the real answer to the balance of payments problem. I have every hope that the momentum of export growth will be sustained and enhanced. If necessary, we must be prepared to restrain domestic consumption to some extent in certain areas in order to release supplies for export.

15. We have resisted the temptation to cope with the short-term difficulties in our balance of payments by ad hoc import regulation through detailed import licensing. Such a process would be self-defeating as it will disrupt the economy, inhibit exports and weaken our attempts at modernisation. The composition of our imports has changed greatly during the eighties. In 1980-81, 65 per cent of our imports consisted of a few bulk commodities like foodgrains, edible oils, fertilizers, petroleum and metals where direct import regulation through foreign exchange allocations is relatively easy. In 1987-88, these bulk commodities accounted for only 33 per cent of our imports. The other imports cover a vast range of raw materials capital goods, chemicals and industrial components. Direct regulation of these through foreign exchange allocations is difficult and could well lead to delays and inefficiency. Hence, the non-bulk import bill has to be managed through more effective use of indirect instruments.

16. Later in this speech I will put before you some measures to discourage low priority imports which go towards the consumption of upper income groups. Kit culture based consumerism is not the objective of our industrial and trade policy and must be discouraged.

17. Industrial policy has an important role to play in stimulating production which can substitute efficiently for imports. Towards this end the Government will ensure that domestic production of items which are imported in substantial quantity is maximised and will re-examine and remove any restrictions which stand in the way.

18. Let me now turn to the special thrust areas in this Budget.

Anti-Poverty Programmes :

19. Successive budgets have sought to tackle the basic problems of poverty and unemployment directly, a process which has been greatly accelerated since 1980-81. In that year, actual expenditure on rural development, social services and food and cloth subsidies amounted to Rs. 1,971 crores in the Central Budget. The greater part of the expenditure in these areas is for directly targeted programmes to improve employment and the earning capacity of the poor and of vulnerable groups like scheduled castes and tribes, and weaker sections, provide them with basic services like education, health-care and water supply, and subsidise some items of essential consumption. In 1988-89 the Budget Estimates provided Rs. 8,652 crores for the same activities.

20. I have not included in this total the expenditure on agriculture and the fertilizer subsidy which has increased from an actual expenditure of Rs. 1,179 crores in 1980-81 to a Budget provision of Rs. 4,343 crores in 1988-89.

21. Under the Integrated Rural Development Programme (IRDP) over 25 million families below the poverty line have been assisted to take up income generating activities. The total investment under this Programme since the beginning of the Sixth Plan has been over Rs. Ten thousand crores, including the term credit provided by the financial institutions.

22. I am happy to inform the Hon'ble Members that under the twin programmes of employment generation for the rural poor, viz., National Rural Employment Programme (NREP) and Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP), 67 crore mandays of employment were generated during 1987-88 as against the target of 50 crore mandays.

23. The present strategy of direct attack on rural poverty through the existing major programmes of self-employment and wage employment will be continued and made more cost effective.

24. Employment is the most urgent need of our people. Much of the employment growth will come from growth in agriculture and in labour-intensive agro-processing industries and services. However, a direct attack on the problem of unemployment is essential. We, therefore, propose to give a special thrust to all programmes of employment generation. It is proposed to merge NREP/RLEGP into a single programme, and to decentralise its implementation. This merged programme will operate throughout the country and will be funded 75 per cent by the Centre.

25. Poverty and unemployment are intense in certain disadvantaged regions and existing employment programmes fall short of needs. Hence, in addition to the reorganised national programme it is proposed to launch a new intensive rural employment programme which will provide additional funds to selected 120 districts which are backward and suffer from acute unemployment.

26. In this year when we are celebrating the birth centenary of Pandit Jawaharlal Nehru, the architect of modern India, there is perhaps no better way of remembering him than to intensify our efforts to remove poverty and unemployment. This programme is a further major step in that direction. It will be named after Panditji to reflect the deepest aspiration of our people.

27. This new programme will allow fuller employment opportunities to at least one member of each family living below the poverty line. The funds for this scheme will be in addition to the provision available to the district under the NREP and RLEGP Programmes. These funds will be merged and locally useful schemes will be taken up to maximise employment opportunities and the creation of productive assets. We hope that the enhancement of the provision for employment through this new scheme will ensure substantial improvement in living standards of the poor and an increase in the productive and socially useful assets in these areas. The details of the programme will be announced later. The provision for this new programme will be Rs. 500 crores in 1989-90. Including this, the provision for employment programmes will be Rs. 1711 crores in 1989-90. I propose to cover the cost of the new programme basically by mobilising additional resources from those who already have substantial incomes and the benefit of gainful employment. I will revert to this later in my speech.

28. We welcome further efforts in this direction by State Governments. Recently, the Constitution has been amended to raise the upper limit for the profession tax to Rs. 2,500. We urge State Governments to use this enabling provision to mobilise additional resources for expanding employment.

29. Additional employment will help poor households to raise their standard of living. But in addition a more direct effort at improving the condition of women and children is necessary. I therefore propose a new programme for the free distribution of saris to destitute women. As for children the ongoing Integrated Child Development Services Programme will be greatly expanded to cover 500 more blocks in addition to over 1700 already covered. This programme is aimed at raising the health, nutrition and educational status of poor children.

30. The total outlay for rural development, social services and on food and cloth subsidies will be Rs. 9374 crores in this Budget.

31. The implementation of anti-poverty and social services programmes takes place largely through State Plans. Many of these programmes are externally assisted. At present 70 per cent of assistance received under externally aided projects is made available to State Governments as additional Central assistance. It is proposed to modify these arrangements to enhance the additional central assistance made available to the States to 100 per cent for assistance received under externally aided projects in the social services sector, and for programmes which have a direct bearing on poverty alleviation. This decision will make available substantially more resources to the States than under the present arrangements, and will facilitate additional investments by them in these vital sectors. Sectors which are expected to benefit from this

decision are Agriculture, Rural Development, Irrigation, Environment, Health, Family Welfare, Nitroton, Woments Development, Education, Housing, Water Supply and Urban Development.

Agriculture

32. Agriculture is the mainstay of our population and a priority sector in our Plans. Today the incidence of taxes on agricultural outputs and inputs is minimal and in fact substantial subsidies are provided both in the Central and State Budgets.

33. As I mentioned earlier, Plan and non-Plan expenditure on agriculture and the fertilizer subsidy has gone up sharply since 1980-81. This year also provision is being stepped up and will reach a level of Rs. 5173 crores.

34. Credit is a major input for agricultural production. In order to increase the flow of credit to agriculture, the target for direct finance to agriculture by Public Sector banks, which was raised last year from 16 per cent to 17 per cent of their total outstanding advances is being further raised to 18 per cent to be achieved by the end of 1989-90. With this change the total credit to be made available to agriculture by commercial banks, Regional Rural Banks and Cooperative Banks will increase by over Rs. 4,000 crores in 1989-90. Hon'ble Members are aware that the rate of interest on crop loans upto Rs. 15,000 was reduced last year and the reduction varied between 1-1/2 per cent and 2-1/2 per cent. With a view to extending the scope of relief, the Reserve Bank of India is today issuing instructions reducing the rate of interest charged on crop loans between Rs. 15,000 and Rs. 25,000 to 12 per cent from the existing maximum rate of 14 per cent.

35. One area of concern is the pace of implementation of irrigation projects in the States. In addition, the gap between the potential created and utilisation of irrigation, leaves much to be desired. The decision to provide higher additionality for external assistance for agriculture and irrigation which I have referred to earlier will add to the funds available for these purposes in State Plans. My hope is that this will help in ensuring better utilisation of aid funds and quicker completion of projects.

36. The rapid growth in incomes in our rural economy will require not merely higher production but also diversification of crops, better post-harvest technology, processing of agricultural products into higher value products, etc.

37. The new Ministry of Food Processing Industries, the first of its kind in the developing countries, was established in July, 1988 to provide for a dynamic relationship between the farmer and industry so that there is better utilisation of agricultural products, greater addition of value to rural produce, generation of massive employment in rural areas, enhancement of the net level of rural incomes and induction of modern technology in the processing of food. Another objective of the Ministry is to promote utilisation of the large scale wastages which take place in the pre and post harvest handling of fruits and vegetables, thereby improving the economic utilisation of food produced as well as enhancing the nutritional inputs available to the people. Later in my speech I will indicate some fiscal incentives to provide a greater stimulus to these industries.

Housing

38. The Government attaches very high priority to housing. It is an activity that meets a very essential need and that is capable of generating a very substantial volume of employment. In pursuance of this, the Government has formulated a comprehensive National Housing Policy. In the field of housing finance several new initiatives were taken in 1988-89. The Reserve Bank of India has liberalised the terms and conditions of housing loans. The Life Insurance Corporation has launched a new scheme known as Bima Niwas Yojana which will enable policy holders to receive financial assistance for purchase or construction of flats.

39. The National Housing Bank has been established and has now become operational. Promotion of a healthy housing finance system and providing adequate finance to the housing sector are the principal functions of the Bank. In formulating its financing policies, the Bank will adopt the motto of the small man first. It has accordingly announced its re-finance scheme in respect of loans given for low income housing of upto 40 square metres. Similarly, in land development and housing projects financed by it, the Bank will ensure that not less than 75 per cent of the plots to be thus developed or houses to be built, will be for those seeking built-up accommodation upto 40 square metres.

40. The prospect of owning a house is a major incentive for saving. We have, therefore, decided to establish a new scheme called the Home Loan Account Scheme which will be launched by the National Housing Bank in cooperation with scheduled banks. To facilitate participation by all segments of the community especially in rural areas, the minimum contribution to the saving scheme is fixed at Rs. 30 per month or Rs. 360 per annum. The savings will earn interest at 10 per cent per annum. Any individual not owning a house anywhere will be eligible to join the scheme. After saving for a minimum period of five years, a member will be eligible for a loan equal in amount to a multiple of the accumulated savings including interest. Specific efforts will be made to link up the Home Loan Account Scheme with the registration for land or house allotment by public agencies. I will propose certain tax concessions for these savings.

Industrial Development

41. Let me now turn to the industrial sector. I have referred to the good performance of the industry and infrastructure sector. We believe that the changes with regard to industrial licensing, price and distribution controls and trade policy that we have made over the past few years have paid rich dividends. The underlying theme of these policy changes is to promote both growth and efficiency by stimulating domestic competition, technology acquisition and modernisation. Our industrial structure is now very complex. Many segments have reached a certain degree of maturity. In this situation it is possible for us to relax many of our detailed regulations and yet remain in control over the direction of development through a judicious use of fiscal and credit policies. In furtherance of this approach, the Government has decided to decontrol the pricing and distribution of cement and aluminium with immediate effect.

42. Since the partial decontrol of cement from 28th February, 1982, the cement industry has witnessed an impressive growth. The production of cement which was 21.01 million tonnes in 1981-82 is slated to increase to 43.5 million tonnes in 1988-89 and 49 million tonnes in 1989-90. Over this period, the levy obligation has been progressively decreased and a fair price for the levy cement has been given. These policies have led to the stoppage of imports since 1985. In fact, the country is now in a position to export cement. Our long term strategy is to increase the production to 65 million tonnes by the end of the Eighth Plan and 87 million tonnes by the end of the Ninth Plan. At present, the levy obligation works out to less than 20 per cent of the total output of the industry. It has now been decided that all price and distribution controls on the cement industry be removed with effect from 1st March, 1989. To ensure the availability of cement at reasonable prices in the remote and hilly regions of the country, a suitable subsidy scheme is being worked out.

43. With the progressive commissioning of the National Aluminium Company (NALCO), India has made great strides in the production of aluminium metal. After achieving a record production of 278,000 tonnes in 1987-88, production in 1988-89 is estimated to go up by 30 per cent to about 360,000 tonnes. During 1989-90 aluminium production is likely to increase by another 20 per cent to reach a level of 435,000 tonnes. NALCO is also exporting alumina and some aluminium and will earn about Rs. 200 crores in foreign exchange during 1988-89. India has thus emerged not only self-sufficient in aluminium metal but will generate exportable surplus in the years ahead. In view of this the Government has decided to decontrol the price and distribution of aluminium with effect from 1st March, 1989.

44. The dispersal of industry to backward areas remains a major plank of our industrial policy. The principal barrier to industrial development in backward areas is the lack of infrastructure. Recently, the Government has announced a new approach to this in the form of the Growth Centre Scheme. In the first phase 61 growth centres will be taken up and provided with infrastructure facilities of a high order. I have provided Rs. 20 crores as the Central contribution for this scheme in 1989-90 Plan and, depending on the pace of implementation, this will be enhanced, if necessary.

45. Let me now turn to the operation of capital markets. A substantial volume of personal savings now flows through the financial instruments traded in this market. In fact, the breadth and depth of our financial structure is an asset that we must use to mobilise savings and channel it into productive directions. Our rural households are showing growing interest in investing in bonds, debentures and shares. However, the provision regarding tax deduction at source is a disincentive. We have already raised the limit below which there will be no tax deduction at source to Rs. 2,500 for dividends. I propose to do the same for interest payments on bonds and debentures.

46. The flow of savings into the Capital Market is directed very much to fixed interest bonds and debentures. However, industrial development also requires risk capital in the form of equity. In order to stimulate the flow of personal savings into equity, the Government intends to introduce an Equity-Linked Savings Scheme. The Scheme will operate through UTI and recognised Mutual Funds and investments will be eligible for tax deductions on the basis of net annual additions to such savings. Details of the Scheme will be announced shortly.

47. The dynamism shown by the industrial sector is to a certain extent the result of our effort to stimulate competition. However, as the industrial environment becomes more competitive, we will need effective measures for coping with the problems of industrial sickness. Some arrangements are in place under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985. However, it is necessary that we take steps before this stage of sickness is reached to encourage and stimulate potentially sick units to rehabilitate themselves. In order to do this, the Government intends to work out an excise relief scheme for weak units to provide them with a proportion of their excise payments as part of a diversification, modernisation or rehabilitation package approved by designated Financial Institutions.

Other Areas

48. Let me now turn to couple of other area where I propose some changes.

49. The Government has been examining the utility of the Gold Control Act to see whether it has served its purpose or not and whether it requires any modification. In the light of this examination the Government proposes to modify the Gold Control Act with a view to keeping a measure of control over primary gold only. This is expected to benefit hundreds of thousands of goldsmiths and artisans who will be able to freely conduct their age-old traditional profession and provide better service to the customers in terms of quality, purity and price. Further this will lead to a boost in the export of gold jewellery which has been stagnant. The details will be worked out and necessary legislation will be introduced soon.

50. I have referred to the need to give a stimulus to savings and have already referred to two measures directed towards this end—the Home Loan Account Scheme and the Equity Linked Savings Scheme. Several initiatives in the area of small savings have been taken in the recent years. I am happy to report to the House that the Indira Vikas Patra, introduced in 1986 and the Kisan Vikas Patra introduced in 1988 are attracting a substantial volume of savings. These two savings instruments do not carry any tax concessions. I propose to introduce a new National Savings Certificate Series VIII which will carry an interest rate of 12 per cent and will be eligible for tax concession under Section 80C but not under Section 80L. The existing National Savings Certificates Series VI and VII will be discontinued. This is part of the process of rationalisation of savings incentives.

51. I am conscious of the need to protect the savings of workers in the provident fund and their right to gratuity. The Employees Provident Fund Act has been modified to raise the minimum contribution to 8-1/3 per cent and this enhanced contribution has taken effect from 1st August, 1988. The Payment of Gratuity Act has been amended to provide for compulsory insurance of gratuity liabilities or the setting up of a gratuity fund under income-tax rules where the pattern of investment will be as prescribed by the Government from time to time. It is proposed to implement these provisions soon after framing necessary rules.

52. As the Hon'ble Members are aware, this Government has in the recent past, taken various measures to help pensioners. The Government is keen to ensure that pension and pensionary benefits are sanctioned and paid promptly and procedures for disbursement simplified. Towards this end, the Government has decided to further simplify the procedure of pension payment to civil pensioners who draw their pension from banks. The proposed simplification envisages that the two intermediary agencies of Accountants General and District Treasuries will not be involved in this work which will be handled by a new Office of Chief Controller of Accounts (Pensions) in the Ministry of Finance. The entire work of pension payment and accounting thereof will be computerised. The new system is proposed to be introduced during 1989-90.

53. I also propose some fiscal relief on family pensions and a new savings scheme for retiring Government employees with certain tax concessions which I will revert to later.

54. Our freedom fighters have made great sacrifices in our struggle for independence. In this year when we are celebrating the birth centenary of one of the greatest leaders of this struggle, it is but appropriate that we raise the pension for freedom fighters to Rs. 750 as a mark of the nation's gratitude.

55. I shall now turn to the Revised Estimates for 1988-89 and the Budget Estimates for 1989-90.

Revised Estimates 1988-89

56. Since the presentation of the Budget for the current year, additional provisions have become necessary for certain inevitable increases in expenditure. Budget support for Central Plan has to be increased by Rs. 771 crores. The increases mainly relate to settlement of claims arising out of crop insurance scheme, subsidy for setting up of industries in backward areas, strengthening of equity base of Power Finance Corporation, payment to Shipping Companies to meet commitments made by the erstwhile Shipping Development Fund Committee and passing on to financial institutions rupee equivalent of external credits extended to them.

57. Central assistance for State and U.T. Plans is expected to be Rs. 421 crores higher mainly due to special assistance that has to be provided to Punjab for financing its Plan outlay.

58. On the non-Plan side an additional provision of Rs. 300 crores is required for export promotion and market development. Subsidy on indigenous fertilizer will also be higher by Rs. 250 crores. A marginal increase of Rs. 200 crores has been made in defence expenditure. An additional provision of Rs. 497 crores will be required for defence pensions on the basis of actual claim arising out of revision of defence pension rates. Grant assistance to States affected by floods has to be increased by Rs. 100 crores. Provision of certain facilities in Punjab necessitated by security considerations has cost Rs. 71 crores.

59. There have been other increases as well. All these would have resulted in a much higher order of increase in non-Plan expenditure and in deficit financing. Government have taken a number of measures to contain the increase in expenditure and improve receipts.

60. Ministries and Departments were instructed to locate savings to meet to the maximum extent possible the increased expenditure including the liability for additional instalments of dearness allowance and bonus sanctioned to government employees during the year. The economy instructions issued last year were continued this year also. As a result of these measures, the increase in non-Plan expenditure has been contained.

61. Gross tax revenue is expected to yield Rs. 776 crores more. The improvement is mainly in Union Excise duties, Customs duties and Corporation Tax. Under non-Tax Revenue the profit on imported edible oils is expected to show a sharp reduction owing to an increase in international prices. Capital receipts are expected to show significant improvement. Total receipts of Government are now estimated at Rs. 67843 crores as against Rs. 66076 crores in the Budget estimates. Total expenditure is estimated at Rs. 75783 crores as against the Budget estimate of Rs. 73560 crores. The overall deficit for the year is now estimated at Rs. 7940 crores. Thus, in spite of the large additional burden thrown on the budget and the various concessions given it has been ensured that overall deficit does not increase substantially.

Budget Estimates 1989-90

62. Next year being the last year of the Seventh Five Year Plan period every effort has been made to ensure that maximum resources are made available for development. Budgetary support for Central Plan including special additional provision of Rs. 500 crores for new economic programmes is placed at Rs. 16964 crores. Internal and extra budgetary resources for Central Plan are estimated at Rs. 17,482 crores. The total Central Plan outlay for 1989-90 will thus be Rs. 34,446 crores against the current year's approved outlay of Rs. 28,715 crores showing a step up of nearly 20 per cent.

63. Hon'ble Members will be happy to note that in real terms the actual outlay in the Central Sector for the five years would be around 115 per cent of the original Seventh Plan outlay.

64. The Central Plan for 1989-90 places a great deal of emphasis on agriculture, rural development and related areas. A new strategy for agricultural planning has been developed on the basis of different agro-climatic regions. The provision for agriculture and irrigation in the Central Plan has been stepped up to Rs. 1408 crores. I also propose allocation of Rs. 495 crores for the Department of Fertilisers.

65. The programmes of Rural Development are central to our Plan strategy. Inclusive of the provision for the new programme, the provision in the Central Plan for this sector has been stepped up by 28.4 per cent. For promoting rural industrialisation, the reorganised Khadi and Village Industries Commission has planned to expand and diversify its activities. Besides identifying 33 new industries for promotion in the current year, 41 other industries will be taken up for development in the future in a phased manner.

66. The provision for social services in the Central Plan is being stepped up to Rs. 3396 crores. The main emphasis in the social welfare programme in the Annual Plan 1989-90 will be on development of services for early childhood care, women's development, prevention of disabilities and rehabilitation of the affected persons. In order to meet these goals, a large expansion is envisaged in programmes like integrated Child Development Service (ICDS), income-generating schemes for poor and destitute women, education, training and economic rehabilitation of disabled persons. Adequate attention will be given to treating awareness regarding the right of women, campaign against the atrocities inflicted on them and also against the social evils like child marriage, dowry, drug abuse, etc.

67. The Seventh Plan has been characterised by a special thrust towards human resources development. The approach, strategies and major thrust areas included in the Seventh Five Year Plan and the priority programmes of the National Policy on Education 1986, taken up in 1987-88 are being continued. Emphasis is given on universalisation of elemen-

tary education, eradication of adult illiteracy, vocationalisation of secondary education, improvement and consolidation of quality and standards of higher education and modernisation and removal of obsolescence in technical education.

68. In order to maintain the tempo of growth that has been attained in recent years, it is necessary that we continue to invest in the expansion and modernisation of our infrastructure sectors. Hence, the outlays in the Central Plan for Power development have been raised by 38.6 per cent, for Railways by 15.6 per cent and for Telecommunications by 56.6 per cent.

69. Major public sector projects in the industrial sector included in the Seventh Plan have either been completed or are expected to be completed in the last year of the Plan. These include the expansion of Bhilai Steel Plant, Stage I of Visakhapatnam Steel Plant, the Aluminium Complex of NALCO in Orissa, the gas based fertilizer plants at Bijaipur, Aonla Namrup III, the Caprolactam project at Udyogmandal, captive power plants at Durgapur, Barauni, Panipat and Bhatinda and the Maharashtra Gas Cracker Complex.

70. In the industry sector adequate outlays have been provided in the Annual Plan 1989-90 for productive schemes and projects of on-going nature which would be commissioned during the last year of the Seventh Plan, as well as for initiating the necessary preliminary action for the Eighth Plan.

71. Central assistance for the Plans of State and Union territory Governments is placed at Rs. 10,850 crores against the current year's Budget level of Rs. 9,714 crores. Total expenditure from Central Budget on Plan account will be Rs. 27,814 crores next year as against current year's Budget level of Rs. 25,714 crores.

72. Government is aware of the extremely difficult circumstances in which our brave armed forces have been carrying out their arduous responsibilities of defending our country. The whole nation owes its grateful thanks to them for ensuring the security of our borders and for bringing credit to our country when called upon to help other friendly countries in their hour of need. At the same time, all of us recognise that there is continuing need for implementing measures for greater cost effectiveness in our expenditure on defence. My colleagues in the Ministry of Defence have already introduced a number of measures to improve the cost effectiveness of such expenditure. Keeping this in view I have provided for a sum of Rs. 13000 crores for Defence during the coming year. I assure the House that Government will not falter in ensuring the highest level of defence preparedness.

73. Provision for food, fertilizer and export promotion subsidies next year is Rs. 7,472 crores against Rs. 6,841 crores in the current year's Revised Estimates. Interest charges next year are estimated at Rs. 17,000 crores against Rs. 14,150 crores in the current year. Grants to States as a result of the recommendations of the Ninth Finance Commission are estimated to be Rs. 612 crores higher than in the current year. An additional provision of Rs. 152 crores has been made next year for expenses in connection with the General Elections. The deficit of Department of Posts is estimated to be Rs. 97 crores higher than in the current year.

74. Every effort has been made to contain the growth of non-Plan expenditure and only the barest minimum provisions have been allowed. Total non-Plan expenditure in 1989-90 is estimated at Rs. 54,347 crores against Rs. 48,877 crores in the Revised Estimates for the current year.

75. Coming to Receipts, Gross Tax Revenue at the existing rate of taxation is estimated at Rs. 49,588 crores. After payment of Rs. 12,054 crores to States as their share of taxes and Rs. 50 crores to local bodies in Union territories as assignment of revenue, the net accrual to Centre is estimated at Rs. 37,484 crores against Rs. 32,652 crores in the current year. Market borrowings are placed at Rs. 7,400 crores against Rs. 7,250 crores in the current year. External assistance net of repayment is placed at Rs. 3,722 crores against Rs. 3,216 crores in the current year. Taking into account the variations in other receipts and expenditure, the overall deficit for next year at existing rates of taxation is estimated at Rs. 8240 crores.

PART B

76. I now turn to my tax proposals for 1989-90.

77. For most people taxation is taxation. I will only say that we raise resources through taxation to fulfil a larger common purpose and seek to return to people a benefit which is greater than the cost they bear.

78. My budget proposals are guided by the objectives and economic perspectives I have outlined earlier. More specifically the proposals are oriented to the following ends :

- Promoting productive employment,
- Protecting the consumption standards of the poor,
- Discouraging non-essential luxury consumption particularly when it is import intensive,
- Providing some relief to middle income taxpayers
- maintaining the tempo of industrial modernisation and growth,
- containing the budget deficit for 1989-90

79. Now I turn to the budget proposals regarding the direct taxes.

80. The Hon'ble Members are aware of the high priority the Government attaches to creation of productive employment. As I mentioned earlier, a number of schemes are already being implemented to generate employment in rural areas to benefit the vulnerable sections of our society. However, we feel that a time has come for taking initiative to make a substantial dent on the problem of unemployment. To this end, as already stated Government proposes to introduce a new intensive rural employment programme, to be called Jawaharlal Nehru Rojgar Yojana. In order to mobilise resources for this programme, I propose to levy a surcharge at the rate of 8 per cent on resident taxpayers with incomes above Rs. 50,000/- from assessment year 1990-91. I am sure that those who are privileged to have employment in a society, where there are so many who are deprived, will not mind this sacrifice in the interest of creating employment for those not so fortunate.

81. The Government has maintained stability in the direct tax rates during the last four years. However, it has often been represented that a 25% tax at the entry point discourages many taxpayers in coming to the tax net voluntarily. Accordingly, it is proposed to reduce the rate of tax of individuals in the entry slab of Rs. 18000-25000 from the present rate of 25 per cent to 20 per cent.

82. This House is aware of the fact that in order to mobilise resources to meet the requirements of the drought in 1987 and its after-effects in 1988, surcharge on income-tax and wealth-tax was levied. I do not propose to continue the Wealth Tax and Income-Tax surcharge from the assessment year 1989-90 and 1990-91 respectively

83. The combined effect of the changes that I am proposing with regard to the employment surcharge and the changing in the rate structure will be such that a person with a taxable income of below Rs. 56,000/- will pay less tax than at present. The entire burden of additional direct-tax will fall on those with a taxable income above Rs. 56,000/- per annum. The revenue effect of this surcharge will be Rs. 500 crores. I have no doubt that the House will welcome this socially progressive measure.

84. With a view to curbing conspicuous consumption, I propose to enhance the rate of expenditure tax under the Expenditure Tax Act, 1987, as applicable to certain hotels, from 10 per cent to 20 per cent. This will yield an additional Rs. 30 crores.

85. I now come to some measures for providing relief.

86. To meet the housing needs of the citizens has always been an important policy objective of the Government. In his Budget Speech for 1987-88, the Prime Minister envisaged a high priority for the housing sector and had announced the decision to set up a National Housing Bank. necessary legislation in this regard has been passed and the National Housing bank has become operation. In order to help the National Housing Bank mobilise resources in its nascent stage I propose to provide that the deposits made in the Home Loan Account Scheme of the National Housing Bank as well as the repayment of housing loan taken from the Bank will qualify for deduction provided under section 80C of the Income-tax Act. The investment will also be exempt from wealth-tax subject to the overall ceiling of Rs. 5 lakhs. Further, the taxpayers will not get a tax concession under section 54E on capital gains if the sale proceeds are invested in the bonds and debentures issued by the National Housing Bank.

87. Poultry farming is emerging as an important activity for enhancing nutrition and providing employment. I, therefore propose to provide tax exemption to the income from poultry farming at the rate of thirty-three and one-third per cent of such income. This measure should go a long way in encouraging investment in this area.

88. Retiring Government employees are often on the look out for investment opportunities with a good post-tax return. With this view, it is proposed to set up a deposit scheme in which a retiring employee may invest the whole or part of his retirement benefits for a block period of three years. The interest on this investment will be free from income-tax. Further, this investment will also be exempt from wealth-tax. The present ceiling of exemption of wealth upto Rs. 5 lakhs in respect of wealth in certain specified forms will also of apply to such deposits.

89. As a measure for providing relief to the widows and heirs of deceased employees, I propose to amend provisions of the Income-tax Act, to provide a standard deduction at the rate of thirty-three and one-third per cent., subject to a maximum of Rs. 12,000/-, for the recipient of family pension also. Similarly, it is proposed to extend the benefit of deduction of Rs. 15,000/- already available to permanently physically handicapped persons, to persons who are mentally retarded.

90. Hon'ble Members are aware that under the Constitution Amendment Act, 1988 the ceiling of tax on professions has been raised from Rs. 250 to Rs. 2,500 per annum with the object of enabling the State Governments to raise additional resources. I hope that the States will take full advantage of this. I propose to provide that this tax be allowed as a deduction in computing the income under 'Salaries'.

91. Following the announcements made in the budget speech for 1988-89, Government has formulated schemes setting up the Exchange Risk Administration Fund and issued guidelines for venture capital companies/funds which provide assistance to new entrepreneurs. In order to extend fiscal

support to these funds, I propose to extend certain tax concession to them.

92. Revenue loss, if any, on account of the proposed relief measures is expected to be made up through better compliance and better collection.

93. By a notification of the President issued on 7th November, 1988, the Income-tax Act stands extended to the State of Sikkim from assessment year 1989-90. In view of some operational difficulties, I now propose to extend the Income-tax Act, 1961 to Sikkim only from the assessment year 1990-91. The Wealth-tax Act and the Gift-tax Act have already been extended from 1990-91 assessment year by the Central Government's notification.

94. I shall now proceed to deal with my proposals relating to indirect taxes.

95. In formulating these proposals, I have been guided by the imperative need for raising additional resources. In doing so, I have taken care to see that items of mass consumption are not unduly affected and that the burden falls largely on relatively affluent sections of the population.

96. As the House is aware, problems of evasion of excise duties through undervaluation and related administrative problems have led to specific rather than ad valorem duties on a large number of commodities. In fact, of the total excise revenue, about 70 per cent is derived from commodities carrying duties at specific rates. In the case of many commodities which are subject to specific rates of excise duty, the duty incidence is substantially lower than what it was when the specific duties were fixed originally. There has to be a system whereby all specific rates are revised upwards periodically keeping in view price increase. I proposed to make a beginning in this regard in this Budget by increasing the existing specific duty rates of a substantial number of commodities by a modest five per cent of current rates with suitable rounding off. I hasten to add that I have taken care to ensure that items of mass consumption are kept outside the purview of this adjustment. The items on which there will be no change in the rate of excise duty include sugar, tea, coffee, petroleum products like kerosene, diesel and motor spirit, biris, vegetable oil, vanaspati, cotton yarn and fabrics, jute yarn and fabrics, and electric bulbs and fluorescent tubes. Similarly the existing exemption for newsprint and specified paper intended for use in the printing of textbooks or other books of general interest remains unaltered.

97. It is expected that the upward revision of specific rates will yield an additional excise revenue of Rs. 220 crores.

98. Some commodities which are charged to excise duty at specific rates and which would call for a higher rate of adjustment than what has been proposed in general. I now come to my proposals in regard to these commodities.

99. In the case of iron and steel, the specific rates of duty have not been changed significantly for over a decade now. As a revenue raising measure, I propose to raise the rates of duty on these items. The duty on pig iron is proposed to be increased from Rs. 80 to 200 per tonne. On steel items other than stainless steel, such as ingots, billets, bars, rods, etc. presently attracting duty of Rs. 365 per tonne I propose to increase the duty to Rs. 500 per tonne. The duty on certain hot rolled flat products such as sheets, strips, etc. is proposed to be raised from Rs. 500 to Rs. 700 per tonne. In respect

of certain cold rolled flat products such as sheets and strips, the duty is proposed to be raised from Rs. 715 to Rs. 900 per tonne.

100. There are certain assessment disputes in the case of forgings and castings as the duty rates vary depending upon the classification. As a measure of rationalisation and to prevent such disputes, I propose to levy uniform rate of duty of Rs. 800 per tonne on steel forgings and Rs. 600 per tonne on steel castings.

101. In the case of stainless steel where the duty incidence is rather low, I propose to raise the duty on ingots, semi-finished products and hot rolled products from the existing rates to Rs. 1000 per tonne and on certain cold rolled products from 715 per tonne to Rs. 1500 per tonne. Stainless steel castings and forgings will also attract a duty of Rs. 1500 per tonne.

102. Similar duty adjustments are proposed to be made on other iron and steel items. In the case of dutiable downstream products, MODVAT credit on iron and steel items would continue to be available.

103. These measures are expected to result in additional excise revenue to the tune of Rs. 150 crores and customs revenue of Rs. 18 crores.

104. No Finance Minister can resist the temptation of looking to smokers of cigarettes for augmenting excise revenue. I must confess that I like most of my predecessors, readily submitted to this temptation. Smokers who do not pay any heed to the statutory warning to their health should, I feel at least contribute more to the health of the national economy. I propose to restructure the duty on cigarettes. While generally the duty rates are being raised, the extent of increase would be more in that case of filter cigarettes of length above 70mm. However, non-filter cigarettes of length upto 60 mm will carry a rate of excise duty of Rs. 1 per packet of 10. These measures are estimated to yield excise revenue to the tune of Rs. 101 crores.

105. Having revised the duty structure on cigarettes, I would not like users of pan masala to feel aggrieved that they have been let down. I propose to double the excise duty presently being levied on pan masala not containing tobacco for the two existing slabs based on value from Rs. 10 and Rs. 20 per kg. to Rs. 20 and Rs. 40 per kg. respectively. Simultaneously, I propose to increase the excise duty on pan masala containing tobacco from 25 per cent to 30 per cent. The revenue implication of these measures is Rs. 8 crores.

106. As the House is aware, molasses is the principal raw material for the manufacture of liquor. In keeping with its end use, I feel, molasses can bear a higher incidence of duty than at present. I accordingly propose to increase the excise duty on molasses from Rs. 60 to Rs. 120 per tonne. I propose to increase suitably the credit of money that is presently available when alcohol is used in the manufacture of chemicals. It is estimated that this measure will yield additional excise revenue to the tune of Rs. 11 crores.

107. I have a couple of proposals relating to travel tax.

108. As present, Foreign Travel Tax is being levied at the rate of Rs. 50 per ticket for travel to neighbouring countries and Rs. 100 per ticket in respect of travel to other countries. These rates have not undergone any change since 1979. I propose to increase the aforesaid rates of tax to Rs. 150 and Rs. 300 respectively.

109. As the House is aware, Government has invested substantial sums of money in developing our airports and providing infrastructural facilities therein. Keeping this fact in view, the privileged few who can afford to fly within the country should not mind if they are to pay a small extra amount as tax for augmenting revenues. I intend to levy a new tax called Inland Air Travel Tax at 10% of the basic fare. However, I propose to exempt passengers paying air fare in foreign currency. There will also be a provision for exempting deserving special categories of passengers from this tax.

110. The proposals relating to travel tax will be given effect to from a date to be notified later and are expected to yield additional revenue to the tune of Rs. 85 crores.

111. Having dealt with those who fly, I now turn to those who drive. Let me deal with my proposals in regard to the automobile sector.

112. As honourable Members are aware, presently there is a concessional rate of excise duty of 25 per cent in respect of fuel efficient cars of engine capacity not exceeding 1000cc and 30 per cent in respect of such cars of engine capacity exceeding 1000 cc as against the rate of 35 per cent for other cars. I feel fuel efficient cars have established themselves and there is no necessity to continue with the concessional rates any more. I accordingly propose to levy a uniform rate of 35 per cent on all motor cars. This rate will apply to vans and jeeps also. The revenue gain from this measure will be Rs. 100 crores.

113. Currently the excise duty on two wheelers of engine capacity not exceeding 100 cc is 15 per cent and that on others, 25 per cent. I propose to restructure the excise duty on two wheelers into a four tier regime. The rate of duty on two wheelers upto 50cc will remain at the present level of 15 per cent. The duty on two wheelers between 50 and 100 cc is being raised from 15 per cent to 20 per cent. There is no change in the rate of excise duty of 25 per cent on two wheelers between 100 and 150 cc. The rate of duty on two wheelers above 150 cc will be 30 per cent. This measure is expected to yield additional revenue of about Rs. 26 crores.

114. I also propose to give some concessions in customs duties to this sector keeping in view the need to encourage domestic production and hasten the process of indigenisation.

115. I further propose to prescribe a concessional duty of 40 per cent on machinery imported for the manufacture of fuel injection equipment, which is a vital component for the automobile sector. The same rate would be applicable to components imported for manufacture of fuel injection equipment. The concessional rate would be available only to the units manufacturing under an approved phased manufacturing programme.

116. The concessions in customs duty to the automotive sector will have a revenue implication of Rs. 19 crores.

117. I now come to the package of measures relating to the electronics sector. This is one of the fast growing sectors in our economy and is in a position to contribute more to the exchequer. My proposals in regard to this sector are oriented to giving a greater stimulus to the process of indigenisation.

118. The Members of the House are aware that television has offered considerable entertainment to our people. It would

be in the fitness of things that television viewers who derive such entertainment should contribute more to the resources of Government and thereby to the programmes of national development.

119. At present, black and white television sets of screen size exceeding 15 cm. and upto 36 cm are completely exempted from excise duty. While continuing the exemption for such sets, I propose to increase the excise duty on the picture tube of such sets to Rs. 200 per tube. Black and white television sets of screen size exceeding 36 cm attract excise duty of Rs. 300 per set. I propose to increase this rate to Rs. 500 per set.

120. As regards colour television sets, the present duty is Rs. 1500 per set of assessable value upto Rs. 5000 and Rs. 2000 per set of assessable value more than Rs. 5000. This duty structure has led to some valuation disputes. Some high value sets have also entered the market. A review of the duty structure on colour television sets is therefore called for. I propose to fix a duty of Rs. 2250 per set without remote control, Rs. 2500 per set with remote control and Rs. 4000 per set having the facility of 'Picture in picture'.

121. I also propose to fix a uniform rate of 20 per cent on radios, two-in-ones, cassette recorders and musical systems, as against the present rates of 15 per cent or 20 per cent.

122. I propose to increase the excise duty on computers from 10 per cent to 15 per cent ad valorem. At the same time computers are being taken out of the general scheme of exemption for the small scale sector.

123. Presently, specified raw materials and piece parts imported for the manufacture of specified electronic components attract customs duty at the rates of 35 per cent and 50 per cent respectively. While extending concessional duty to a larger number of items, I propose to raise these rates to 40 per cent and 60 per cent respectively.

124. These proposals relating to electronic items are estimated to yield additional revenue to the tune of Rs. 158 crores in excise and Rs. 36.5 crores in customs.

125. I have some concessions in customs duty to announce for the electronics sector. In last year's Budget, a uniform rate of import duty of 100 per cent was provided to a large number of equipments for telecommunication, satellite communication, data communication, television transmission and sound broadcasting. I propose to extend the concession to 35 more specified equipments.

126. Optical communication cables are essential for telecommunication. In order to encourage the manufacture of such cables in the country, I propose to reduce the import duty on specified raw materials required for their manufacture from the present rates varying from 130 to 300% to the level of 80%.

127. With a view to encouraging production of high-tech items like large scale integrated circuits, microprocessors and other microelectronic items, 22 items of machinery have been given a concessional import duty of 15%. I propose to extend the concession to five more items of machinery.

128. The concessions in customs duty to the electronic sector will have a revenue implication of Rs. 33 crores.

129. I have a package of measures in regard to the customs duty structure for capital goods.

130. At the time of presenting the 1987 Budget, the Hon'ble Prime Minister had emphasised the importance of the capital goods industry and had stated that it is central to our efforts for achieving self reliance and to promote the growth of this sector, important steps were initiated that year. The success brought forth by these measures encourages us to continue further along those lines. My first proposal is to extend the duty concession for import of machinery under the technology upgradation scheme for the capital goods industry to four more sectors. These are cutting tools, commercial tool rooms, textile machinery and paper machinery. In addition, for the machine tool sector, I propose to expand the list of machinery items attracting concessional duty.

131. I propose to rationalise the import tariff of capital goods. The rate of import duty on general projects and machinery is being reduced from the existing 90% to 80% ad valorem. The rate of duty on components which is 15% below the rate applicable to the machinery would get correspondingly reduced.

132. The next step in this regard would be rationalising the rate of concessional import duty on specified machinery which presently varies between 25% to 35%. This is being unified and fixed at 40% ad valorem. There would, however, be no change in the case of fertilizer projects. In the case of power projects, the increase would be by five percentage points.

133. The rationale for these changes lies in the desirability of reducing the dispersion in tariff rates as much as possible. In pursuit of this objective, I am introducing an intermediate level of duty of 60% ad valorem. This will apply to certain specified items of machinery which are manufactured indigenously such as captive power plants, certain types of generating sets and circular looms for jute industry.

134. As a measure of facilitating the export thrust sectors to upgrade their technology by importing modern machinery, concessional duties have been prescribed from time to time on machinery for specified thrust sectors. I propose to extend the concession to rubber and canvas footwear sector and to expand the existing list of machinery for textile and sericulture sectors.

135. These measures relating to capital goods are estimated to result in a loss of customs revenue of about Rs. 117 crores.

136. As I have mentioned earlier in my speech, pricing and distribution of aluminium is being decontrolled with immediate effect. In this context, I propose to increase the excise duty on aluminium ingots and wire-rods from the existing level of 18% to 20% ad valorem plus Rs. 2500 per tonne. Since MODVAT credit in regard to primary aluminium would be available for dutiable downstream products, I propose to increase the duty on most of such products by ten percentage points. It is also proposed to exempt aluminium ingots from basic and auxiliary duties of customs. The basic customs duty on aluminium scrap is being reduced from 30% to 15%. The net revenue yield from these measures will be Rs. 50 crores.

137. There are certain commodities which attract a low rate of customs duty at present and these call for a review. I propose to raise the import duty on wood pulp, waste paper, low ash coal, raw petroleum coke and certain chemicals by five percentage points over the existing rates. On benzene, I propose to raise the basic customs duty from the

existing nil rate to 25% ad valorem. The revenue gain from these proposals will be Rs. 39 crores.

138. I propose to increase the basic customs duty on glazed newsprint from Rs. 550 per tonne to 30% ad valorem. This will yield additional revenue of about Rs. 12 crores.

139. Watches and components thereof presently bear a low rate of excise duty of 2% ad valorem. This rate was fixed in order to encourage indigenous production of watches. This measure has been successful. I think the time has come when the watch industry can bear a higher duty. I propose to increase the rate to 5% ad valorem. This will result in a revenue gain of Rs. 5 crores.

140. I shall now deal with my package of proposals in regard to the agro-based and related industries.

141. As Honourable Members are aware, the growth of food processing and packaging industry is essential for increasing value addition of agricultural produce and raising incomes of farmers. As part of Budget proposals last year, excise duty on parts and accessories going into the installation of cold storage plants for preserving foodstuffs was reduced from 40% to 15%. I now propose to extend the concessional rate of 15% to parts of refrigerating appliances and machinery as well as compressors intended to be used in refrigerated vans meant for transport of food and dairy products.

142. At present, 34 specified items of food processing and packaging machinery enjoy a concessional import duty of 35%. I propose to extend the concessional rate to a few more specified items of machinery such as transport refrigeration unit and machinery for egg processing. The concessional rate of duty as stated earlier is now being fixed at 40%.

143. I propose to reduce the excise duty on skimmed milk powder and condensed milk from 15% to 10%. Simultaneously the exemption from excise duty on skimmed milk powder in one kilogram pack is being withdrawn. The excise duty on certain other food preparations such as preparations of fish, meat, tapioca and sago in unit containers is being reduced from 15% to 10%. Namkeens such as bujiyas and chabena and specified ready-to-cook mixes such as idli-mix and vada-mix are being fully exempted from excise duty.

144. A concessional import duty of 61% has been provided for certain specified items of machinery for marine food sector. I propose to further reduce the rate to 40% and enlarge the list by adding three more items of machinery for fishing. In addition, I propose to reduce the import duty on machinery for the manufacture of fish nets from 90% to 40%.

145. One of the proposals contained in the New Policy on Seed Development announced in September, 1988 relates to the reduction of import duty on machines and equipments used for seed production and processing and quality control for which technology upgradation is necessary. I propose to prescribe a concessional import duty of 40% on 12 specified items of such machinery and equipments.

146. In order to help improve the quality of poultry feed, I propose to reduce the import duty on two specified amino acids from the present level of 147.25% to 70%.

147. To give relief to the jute industry, I propose to exempt from excise duty jute yarn supplied to a registered handloom cooperative society or an organisation set up or approved by the Government. This exemption will be available for the purpose of development of handlooms for manufacture of fabrics other than those used for jute sacks. I also propose to extend this exemption to units set up by the Khadi and Village Industries Commission and Boards.

148. Paper and paperboard containing not less than 75% by weight of bagasse is totally exempted from excise duty. In order to further encourage the use of unconventional raw materials for the manufacture of paper and thus reduce the pressure on forest based raw materials, I propose to extend full excise duty concession to those varieties of paper and paper board which contain not less than 75% of pulp made from raw jute or mesta. This measure may incidentally help the jute industry.

149. For helping the farmers to get better prices for their produce, I propose to increase the basic customs duty on cinnamon from Rs. 20 per kg. to 90% ad valorem plus Rs. 20 per kg. and that on cloves from Rs. 60 to Rs. 95 per kg.

150. To give a major thrust to marketing of products of the Khadi and Village Industries sector, I propose to make an exception in regard to availability of small scale concession where the products bear the brandname of Khadi and Village Industries Commission and Boards. The existing concession for products of village industry marketed by or with the assistance of the Khadi and Village Industries Commission is being extended to furniture and ceramic products.

151. These measures relating to agro-based and related industries are estimated to result in a revenue loss of Rs. 5 crores of customs duty and Rs. 8 crores of excise duty.

152. On a review of the excise duty structure for the match industry, I feel there is need for revising the duty rates for the different sectors of the industry. Currently, excise duty is being levied on the mechanised, semi-mechanised, non-Mechanised and cottage sectors of the industry at Rs. 5.85, Rs. 4.15, Rs. 3.50 and Rs. 1.60 per gross of boxes respectively. I propose to bring down the aforementioned rates to Rs. 4.50, Rs. 2.00, Rs. 2.50 and Rs. 1.10 per gross. Simultaneously, I propose to increase the excise duty on potassium chlorate, an essential raw material for the manufacture of matches, from 15% ad valorem which works out to roughly Rs. 2 per kilogram to Rs. 5 per kilogram. The duty rates will be converted into metric system and specified as applicable to 100 boxes with effect from the 1st June, 1989. These proposals involve a revenue sacrifice of Rs. 11 crores excise duties.

153. In view of the shortage of cotton due to drought, as part of the Budget proposals last year, a concessional duty of Rs. 5.22 per kg. was prescribed on viscose staple fibre for blending with cotton. However, with the increased availability of cotton this year, there is no further necessity to continue the concession. I propose to withdraw the concessional rate and fix a uniform rate of Rs. 8.35 per kg. on viscose staple fibre. The revenue gain from this measure will be of the order of Rs. 14 crores.

154. I propose to exempt raw wool to be imported by Khadi and Village Industries Commission and State Khadi and Village Industries Boards from the whole of the duty.

155. The customs duty on raw silk is being reduced from 75% to 50% ad valorem.

156. Dyestuffs are important inputs for the processing of textiles. This commodity carries at present an excise duty of 35%. I propose to reduce the excise duty on synthetic organic dyestuffs from 35% to 30%. This proposal which will benefit this textile related industry involves a revenue loss of Rs. 19 crores.

157. Synthetic shoddy blankets of value upto Rs. 60 per square metre are being exempted from the whole of excise duty.

158. I propose to give certain concessions in customs duty to specified life saving drugs and drug intermediates. The proposals in this regard are likely to result in a revenue loss of about Rs. 7 crores.

159. In order to give relief to cement units using vertical shaft kiln, I propose to reduce the excise duty on cement manufactured by such units by Rs. 100 per tonne from the general effective rate. This involves a revenue loss of Rs. 10 crores.

160. As a step towards energy conservation, I propose to reduce the excise duty on high pressure sodium vapour lamps from 15 per cent to 10 per cent. Simultaneously, I propose to prescribe a concessional import duty of 50 per cent on four specified inputs for the manufacture of such lamps. These measures are estimated to result in revenue loss of Rs. 2.5 crores in excise revenue and Rs. 5 crores in customs revenue.

161. There have been representations that the film industry has been adversely hit by video piracy. I accordingly propose to restructure the excise duty rates on feature films. As per the revised proposal, the first 30 prints of each feature film would be eligible for complete exemption from excise duty as against the first 12 prints at present. The rates of duty on subsequent prints are being reduced.

162. Some of the organisations engaged in the rehabilitation of physically or mentally handicapped persons undertake manufacturing activity for providing employment to such persons. Presently, such organisations are eligible for excise duty exemption only to the extent available for specified goods manufactured in the small sector. I propose to fully exempt such goods produced by these organisations.

163. In order to promote safety in chemical industry and environmental control, I propose to extend concessional import duty of 40 per cent on 25 specified equipments such as monitoring instruments for toxic and hazardous, chemicals or gases special incinerating systems etc.

164. Paraxylene is an important raw material used in the manufacture of DMT and PTA which in turn are used by the polyester industry. Keeping in view the recent trends in the international price of paraxylene, I propose to reduce the import duty on paraxylene from 120 per cent to 90 per cent.

165. There are a few rationalisation and anti-evasion measures relating to customs and excise duties.

166. Presently, petro-chemical factories are eligible for certain concessions including concessional excise duty on naphtha when they are declared as refineries. The present scheme

has been reviewed and I propose to make available the concessions with certain modifications, without linking the concessions to the declaration of a factory as a refinery. Simultaneously, I propose to raise the concessional rate of duty on raw naphtha from Rs. 30 to Rs. 50 per kl. The orders declaring certain factories as refineries are being rescinded.

167. Small scale units are allowed complete exemption from excise duty upto a value of Rs. 30 lakhs in case they manufacture goods falling under more than one heading of the Central Excise Tariff. I propose to restructure the scheme so that the exemption upto Rs. 30 lakhs is available only if the goods falling under more than one Chapter of the Central Excise Tariff are manufactured.

168. The details of the revenue implications of the measures announced are given in the Explanatory Memorandum to the Finance Bill.

169. Provision is being made in the Finance Bill for continuance of auxiliary duty of customs and special excise duty at the existing rates.

170. Apart from the above proposals, I have proposed certain amendments in the Finance Bill seeking to effect changes in the excise and customs tariffs. These amendments are merely enabling provisions and have no revenue significance. Besides, there are proposals for amendment of some of the existing notifications. In order to save the time of the House, I do not propose to recount them.

171. In the aggregate, the proposals in regard to changes in the customs and excise duties outlined above are likely to yield additional revenue of Rs. 863.20 crores from excise duties and Rs. 117.06 crores from customs duties. The concessions and reliefs announced aggregate to Rs. 237.12 crores on the customs side and Rs. 71.02 crores on the excise side. The net additional revenue from excise duties would thus be Rs. 792.18 crores. On the customs side, there is a net revenue loss of Rs. 120.06 crores. Besides, the changes in the Foreign Travel Tax and the levy of Inland Travel Tax would yield an additional revenue of Rs. 85 crores. Thus, out of the total net additional yield of Rs. 757.12 crores from indirect taxes, the Centre's share would be Rs. 373.13 crores and that of States Rs. 383.99 crores.

172. The Medicinal and Toilet Preparations Act is an enactment under Article 268 of the Constitution in terms of which duties are levied by the Union but collected and appropriated by the States. There has been no change in the rates of duties leviable on medicinal and toilet preparations containing alcohol, narcotics and narcotic drugs since 1982. There have been requests from the State Governments that the rates should be reviewed and revised suitably. While I do not propose to make any changes in the ad valorem rates, do not propose to make any changes in the ad valorem rates, of the existing rates. The details of the changes made in the Schedule are given in the Explanatory Memorandum to the Finance Bill.

173. Copies of notifications giving effect to the changes in customs and excise effective from 1st March, 1989 will be laid on the Table of the House in due course.

174. The modifications proposed by me in direct and indirect taxes are expected to yield Rs. 903 crores to the Centre. Taking this into account the year and deficit for the next year is estimated at Rs. 7337 crores.

175. Sir, the proposals I have just presented mark, in their totality, a qualitatively new stage in our continuing quest for social justice. The new employment programme, which will expand over time, is the people's own weapon in their struggle to usher in a society liberated from the shackles of poverty. The budget proposals also reflect Government's strong commitment to self-reliance. We are determined to vigorously implement strategies for export promotion, for modernisation of Indian industry and for efficient import substitution. Within these basic policy parameters, every effort will be made to contain imports to reasonable levels. The journey along the path of development is hard and long. It involves sacrifices. The question is who will make such sacrifices for future growth and prosperity. The answer of these budget proposals is clear and categorical. It is the relatively affluent who will have to share a larger burden so that the weaker and vulnerable sections of society may share in the fruits of growth.

176. I commend the Budget to the House.

K.V.R. NAIR, Addl. Secy. (Budget)

